श्री संतोष बागड़ोदिया : सर, दो मिनट अभी नहीं हुए हैं। It is a serious matter, Sir. The House is being misguided by the Leader of the Opposition.

MR. CHAIRMAN: But, he is not here.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: The sender is one Senator, Mr. Thomas Graham, and the recipient is Mr. Harry Barnes. I have personally dealt with Mr. Harry Barnes. Harry Barnes का जो लेटर मेरे पास आया, मैं उस को कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है "First of all, I should know that I know of no Senator, Thomas W. Graham. I do know of Thomas Graham, who, in the 1990s worked at the Rockefeller Foundation in New York. There was no Senator, I have also enquired, never in the history of the USA. Thomas W. Graham नाम का कोई सेनेटर कभी बना ही नहीं। दूसरी बात, उन्होंने कही है, "Secondly, I have no recollection of the specific communication you mentioned coming to me in 1995 or at all for that matter. इस मैटर के बारे में भी नहीं है, 95 में भी नहीं आया। यह हाउस को misguide कर रहे हैं, इसलिए इस का नोटिस लिया जाय। मेरा अनुरोध है कि इसे प्रिविलेज कमेटी को दिया जाए।

श्री सभापति : आप ने अनुरोध कर लिया, मैं देख लूंगा। श्री नारायणसामी, आप बोलेंगे?

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Let Mr. Datta Meghe speak, Sir. I will speak after him. He wants to speak on Vidarbha.

SHORT DURATION DISCUSSION

Suicide by the farmers in various parts of country and demand to increase the Minimum Support Price of foodgrains

श्री दत्ता मेघे (महाराष्ट्र) : सभापति महोदय, देश के विभिन्न भागों में किसानों द्वारा की जा रही आत्म-हत्या तथा खाद्यानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के बारे में बहस चल रही है। सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है।

श्री सभापति : माननीय बागड़ोदिया जी, आप ने जो पेपर्स बनाए हैं, जो पेपर्स आप रेफर कर रहे थे, वे सब मुझे दे दीजिए।

श्री दत्ता मेघे : महोदय, हमारी जनसंख्या के 65 प्रतिशत लोग अभी भी कृषि या कृषि से संबंधित व्यवसाय से जुड़े हैं। हमारे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की चौथाई हिस्सेदारी है, जो अब धीरे-धीरे कम हो रही है। आज कृषि और किसान - दोनों की हालत बहुत गंभीर है। आज किसान गरीबी, बीमारी और कर्ज से दबा हुआ है और आत्महत्या तक कर रही है।

सभापति महोदय, हमारे नेता जिनके भरोसे में इस हाउस में आया हूं, पिछले 30 साल से पॉलिटिक्स में हूं। श्री शरद पवार किसानों के बारे में और खेती के बारे में बहुत गंभीरतापूर्वक सोचते हैं। मैं 35 सालों से उन्हें बहुत नजदीक से जानता हूं। उन्हें इस बारे में पूरी कल्पना है।

[उपसभाध्यक्ष (प्रो0 पी0जे0 कुरियन) पीठासीन हुए]

महोदय, पहली बार देश के प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री जी हमारे विदर्भ एरिया में आए और वे किसान जिन के घर में आत्म-हत्या हुई, उन सभी से मुलाकात कर डायरेक्ट बात की। उन के बीच में कोई नेता और कोई गलत आदमी नहीं था। इसलिए हमारे प्रधान मंत्री देश के पहले प्रधान मंत्री हैं, जो किसानों के साथ जहां-जहां आत्महत्या हुई, उन गांवों में गए और वहां जाकर उन सभी से बात की। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी ने किसानों को 3750 करोड़ रुपए की राहत दी है। उसमें से किसानों के कर्ज माफी हेतु 712 करोड़ दिया गया है। नए कर्ज हेतु तथा कर्ज पुनर्रचना हेतु 1296 करोड़ रुपए दिए हैं। सिंचाई के विकास के लिए प्रलंबित प्रकल्प के निर्माण हेतु 2177 करोड़ दिया है। छोटी सिंचाई के लिए 318 करोड़ दिया है। प्रमाणित बीज के लिए 180 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय फलदान मिशन के लिए 225 करोड़ रुपए किसानों को पर्याय उद्योग हेतु 135 करोड़ दिए हैं और आपात काल के लिए हर जिलाधिकारी को 50 लाख रुपए देने की बात कही है। यह पहली बार हुआ है।

कुछ लोग कह रहे थे कि विदर्भ में यह बात हुई। लेकिन यह सिर्फ विदर्भ में या महाराष्ट्र में ही नहीं हुई, बल्कि यह पैकेज आन्ध्र, केरल और कर्नाटक में भी दिया जा रहा है। यह पहली बार हो रहा है। सभापति महोदय, यह जो पैसा आ रहा है, उसका सदुपयोग हो, उसका इम्प्लिमेंटेशन हो, मैं आपसे इसके लिए गुजारिश करूँगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, विदर्भ आज एक ऐसा पिछड़ा हुआ प्रदेश है, जो पहले नागपुर शहर की राजधानी था। जब संयुक्त महाराष्ट्र बना, तो यह उसमें शामिल हुआ। उस समय भी इसे विशेष दर्जा दिया गया था। 371(2) के कालम के अनुसार हमारे विदर्भ को यह दर्जा दिया जाएगा। इस धारा के अन्तर्गत कुछ वर्षों पहले विदर्भ विकास हेतु स्वायत्त विकास मंडल बने हैं। इस विकास मंडल में भी राज्यपाल द्वारा ऑर्डर देने के बाद हमारे जो पैसे आने थे, वे नहीं आए हैं। यह हमने देखा है। प्रधान मंत्री जी जब विदर्भ में आए, उसके पहले स्वामीनाथन जी, जो कृषि के एक तन्य हैं, उनको भेजा गया। बाद में पंत प्रधान हाउस से मिश्रा जी मैडम, जो नियोजन समिति की अध्यक्षा थीं, वे वहाँ पर गईं। उन्होंने पूरा अध्ययन करने के बाद, जो भी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी, उसका इंप्लिमेंटेशन नहीं हुआ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि किसानों की आत्महत्या--- 11 जिलों में से 6 जिलों में कपास और ज्वार पैदा होता है और बाकी के जिलों में अभी चावल होता है। हमारे यहाँ 11 जिले हैं और छः जिलों में यह पैकेज दिया गया है। उनकी बराबरी की हालत है। गढ़चिरौली जिला, गोंदिया जिला है, इन जिलों में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी और कृषि मंत्री जी के आने के बाद भी वहाँ 105 किसानों ने आत्महत्या की है। पैसे अभी सैंक्शन हुए हैं और महाराष्ट्र सरकार को गए हैं। लेकिन किसानों को जो लाभ प्रत्यक्ष रूप से मिलना था, उसमें थोड़ी-बहुत दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन हमारे कृषि मंत्री जी को मालूम है कि कहाँ पर क्या दिक्कत है? जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उसको जो बड़े पैमाने पर पैसा आया

है, उसे छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं में लगाना है। इसके लिए भी हमारे कृषि मंत्री जी सतर्क हैं। यह मुझे मालूम है।

आज पूरे विदर्भ में जो भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वे क्यों कर रहे हैं? एक तो जो उनके उत्पादन पर जो खर्च आता है, वह कीमत उन्हें नहीं मिलती है। हमारे यहाँ कपास का जो उत्पादन करने वाला किसान है, उसके लिए एक एकाधिकार योजना थी, जो अच्छी थी। मार्केट में उनको ज्यादा पैसा मिलता है, तो वे मार्केट में जाएँगे। लास्ट ईयर वह जो स्कीम थी, उसमें कम कपास आया, लेकिन उन किसानों को फायदा हुआ। हमारे शरद जोशी जी यहाँ बैठे हैं। वे एकाधिकार के खिलाफ बहुत बोलते थे, लास्ट ईयर उनका फायदा हुआ। लेकिन वे किसान, जिनको पैसा मार्केट में नहीं मिलता, तब उनको इस योजना का फायदा होने वाला है। सरकार ने ये दोनों योजनाएँ वहाँ रख दी हैं। सर, हमारे किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनमें SC के 16 परसेंटट हैं, ST के 11 परसेंट हैं, VJNT[7] के 17 परसेंट और OBC के 6.40 परसेंट लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जब हम देखेंगे, तो जो किसान आत्महत्या करता है, उनको बैंक से कर्ज़ा नहीं मिलता। कम हो गया। हमारे यहाँ विदर्भ के जो बैंक थे, सब बंद हो गए। वे पैसा भी नहीं दे रहे हैं और केवल वसूल करने का काम कर रहे हैं। जो बैंक हैं, वे भी रिजर्व बैंक की तरफ़ से पैसा नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमारे जो किसान हैं, वे प्राईवेट मनी लेंडर्स से पैसा लेते हैं, जिनका ब्याज 25 टके से 40-50 टके तक जाता है। जब वह किसान उनका पैसा नहीं देता है, तो मजबूरी में, दोनों ओर मार होती है- अकाल हुआ है, अभी ज्यादा पानी हुआ है। किसान बुआई करता है, फसल पैदा करता है, लेकिन उसको पैसा नहीं मिलता है। फिर शादी हो या बच्चों की एजुकेशन हो या परिवार की हेल्थ का मामला है, उसके लिए वह बहुत तकलीफ में आता है। पूरे देश के अंदर हमने देखा कि एक लाख से ऊपर इन्होंने आत्महत्या की है। यूपीए सरकार ने इनके लिए बहुत अच्छा काम किया है, वहां गए और स्थिति को देखा। जहां तक आत्महत्या की बात है, यह नहीं होनी चाहिए, इसके लिए प्रयास भी किया। इस प्रयास के लिए मैं पंथ प्रधान जी और शरद जी का बड़ा स्वागत करता हूँ।

महोदय, हम लोग जहां से आते हैं, वहां के किसान मर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो हालत है, वह बहुत खराब है। हमारे शरद जोशी वहां एक नेता हैं, बीच में आंदोलन करते हैं और बाद में चले आते हैं। शरद जी आप भी विदर्भ के हैं, वहां रहिए और किसानों के हित में रहकर आप आंदोलन चलाइए, हम आपके साथ में हैं, लेकिन बीच में छोड़ मत दीजिए। ...**(व्यवधान)**... आप छोड़ देते हैं, इसलिए किसानों को तकलीफ हो रही है। यह नहीं होना चाहिए। आज हमारे विदर्भ के अंदर किसान राहत के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ देख रहे हैं। हमारे देश के कृषि मंत्री, इनको मैं 35 साल से जानता हूँ, इनके साथ में मैंने काम किया है। इनको विदर्भ की हर तहसील, ताल्लुका, ब्लॉक की पूरी जानकारी है, इसलिए मैं अनुरोध करुंगा कि जो पैसा आया है, वह जल्दी से जल्दी हमारे किसान भाइयों को मिले, ताकि वे आत्महत्या न करें, उनको रोजगार, धंधा मिले। वहां का जो वातावरण है, वहां पशु के लिए प्रोब्लम हो सकता है, चारा नहीं मिलता है, इसलिए आप पशुओं के लिए और दूसरी जो आपकी योजनाएं हैं, जो हमारे चार जिलों में रखी हैं, लेकिन दो-तीन जिलों में नहीं रखी हैं, इसके लिए मैं आग्रह करुंगा कि जहां नहीं है, वहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

महोदय, आखिर में मैं पंथ प्रधान जी और शरद जी का तहेदिल से स्वागत करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि जिन-जिन योजनाओं का किसानों के लिए जो-जो पैसा है, वह पैसा किसानों को जल्दी पहुंचे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the very important subject of farmer suicides. It is a major concern for the Government of India and also the State Governments. The kind of efforts made by the UPA Government to see that there is no suicide by the farmers and the kind of scheme they have announced, have now started yielding results.

Sir, the hon. Agriculture Minister himself is a farmer. He knows about the problems of the farming community better. Most of the hon. Members have spoken on this issue, highlighting various issues. I am not going into those issues. Sir, I would like to submit three or four important issues. Sir, the hon. Agriculture Minister will agree with me that there is no strategic investment in the agricultural sector for irrigation and creating infrastructure for the farmers. Sir, hardly 0.5 per cent of the Gross Domestic Product is being utilised for creating infrastructure for the farmers, namely, the irrigation facilities, the transport facilities for the farmers, providing them electricity connection for the pump sets, which is very meagre. In developing countries, it goes more than two or three per cent; in developed countries, it is beyond. Sir, there is lot of criticism. An argument has been coming forward that the subsidies that have been given to the farmers - whether it is a subsidy in the form of seeds, fertilisers and also the farm subsidy that has been provided - slowly one by one they have been withdrawn, saying that now, we are going in for modernisation, urbanisation and also globalisation. Sir, all political parties are claiming that they are for the farmers because farmers are the vote bank. But, when it comes to the question of the implementation of various programmes for the farmers, we are not paying due attention. That is the reason for the farmers committing suicides. Sir, if we go through the history, we will find that suicides are taking place in those areas where cash crop is raised by the farmers. Whether it is in Andhra Pradesh or in Maharashtra or in Karnataka or in the border areas or in parts of Gujarat and Orissa, it is a matter of great concern. The other day, the hon. Finance Minister said in this august House that the Government has earmarked Rs.1,75,000 crores for giving credit to the farmers. This is on record. But, practically, they are not getting this money. I have also asked the hon. Finance Minister whether he has any monitoring mechanism to see that this money is being properly

utilised by these bank officers and is being provided to the people who really belong to the farming community. He said, "I cannot go to all the banks to see that. It is practically not feasible for the Finance Minister." Then, I told him that he has a monitoring mechanism at the State level, and also at the district level, to see that the real farming community gets the benefit. I have the personal experience because the people are coming to me, the farmers are coming to me; they are narrating the problems being faced by them in getting the loans. The Minister says, "Without security the loan cannot be given because they are land owners." For the purpose of raising the crop when they go to the banks, hundred questions are being asked by the bank managers and they get frustrated. Then, they go to the moneylenders. They become the victims of those shackles. This is the major concern.

Another point is regarding the cooperative banking system. The cooperative banking system has become a total failure. It may be working well in Maharashtra or in some parts of the country. But, in other parts of the country, it has become a fiefdom of only a few people. They are cornering everything. In the cooperative banking system, the person who has got the money power and the muscle power, is enjoying everything. It is not going down the line. This is happening in actual practice. The hon. Agriculture Minister knows all this.

Then, Sir, I come to the marketing mechanism. Marketing mechanism is very important. The position of the farming community position is like this. Farmers depend upon their land for their livelihood. They do not have any other source of income. They raise their crop after taking loans from the banks. They educate their children, build houses for their family members and perform various ceremonies/functions. All that is done by them with the money that is accrued to them only from the farm cultivation. And, ultimately, the question of investment in agriculture arises before them. Since they spend the money for performing various social functions, for educating their children, running the family and constructing their houses, they become penniless. Then they opt for taking the loans. When the public sector banks and the cooperative banks do not come forward to help them, then, they go to the moneylenders.

Through the Green Revolution, we have got very good results. Thereafter, there should be a focus on increasing the production. In the adjoining countries like Myanmar, the production of paddy, per hectare, is more than the production of India. In China, it is 29 per cent more than

the production of our country. China is able to produce more, but India is producing less. Then, why will not our farmer go into indebtedness? This is the situation.

Now, I come to research and development. What is the amount of investment being made in agriculture? Our farmers are capable of adopting the new technology. They are capable of adopting, but, unfortunately, Sir, after the research work is done, then, it takes a minimum of six or seven or ten or fifteen years for the new technology to reach them, and by that time, it becomes obsolete. Then, that technology is of no use. This is the state of affairs prevailing there.

Now, I come to crop insurance. The Crop Insurance Scheme was started by this Government and the previous Governments. But, it is not being uniformly implemented in all the States. They are doing it in a pick and choose manner. Sir, why can't we make the crop insurance compulsory for the farming community? The Government can contribute; the State Governments can also contribute. We become responsible when we say that the Government has to safeguard the interests of the farmers. Why can't the Government contribute as far as the insurance for the farming community is concerned? I want the hon. Minister to consider this aspect.

Sir, there are various other issues. As far as the farmer's problems are concerned, they are enormous. The hon. Minister has mentioned about the Minimum Support Price. Four Members have raised this issue. The kind of mechanism that they have evolved for the purpose of arriving at the price of the product is itself faulty. That has to be taken care of by the hon. Minister. Ultimately, when it comes to the question of agriculture, we say that the farmers are the backbone of the country. Seventy-five per cent of the people of this country are dependent on agriculture. But we give less importance to agriculture. That is the thing. Surprisingly I find in this august House that most of the industrialists have become farmers. They have started speaking in support of the farmers. I welcome that. I am very happy about that. I want them also to feel how the farmers are suffering and how we can mitigate the sufferings of the farmers.

Then there is the question of cooperative marketing. Cooperative marketing is also a failure. Why? It is because of hoarding, black-marketing and distress sales by the farmers. Distress sale is also one of

the major reasons why farmers are suffering. When some crop is produced, the farmers sell it at a lower price. There is distress sale. The businessmen earn a lot of money after some time. These are the various cumulative effects that lead the farmers to commit suicide. In Vidarbha, the farmers committed suicide. In Andhra Pradesh also, the farmers committed suicide. They are our brothers and sisters who have been suffering. Simply if someone tells a man that he is indebted and he has not paid the money to the moneylender, because of family pride he feels aggrieved and goes to the extent of committing suicide. It is a very serious matter.

A package has been announced by the hon. Prime Minister and support has been given by the Agriculture Minister. I welcome that. But, once and for all, the Government has to find a mechanism and come to the help and assistance of farmers right from the day they start cultivation till the day they sell their products.

There is a package by the Government of India and it should be followed by various States. It is not the responsibility of the Central Government alone. The State Government has also a share in it. The State Government has also to cooperate with the Central Government. Therefore, I want the hon. Agriculture Minister to consider all these aspects and give us a very clear reply as to how the Central Government will come to the help of farmers and ensure that the farmers' families flourish in this country.

श्री वरिन्दर सिंह बाजवा (पंजाब): धन्यवाद सर, आज हम हाउस में भारत के किसानों के द्वारा जो आत्महत्याएं हुई हैं, इस विषय पर डिस्कशन कर रहे हैं।

सर, इसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं और पहले भी मैंने हाउस में यह सवाल उठाया था कि पंजाब के अंदर किसानों के द्वारा 5000 से भी अधिक आत्महत्याएं हुई हैं। अकेले संगरूर डिस्ट्रिक्ट में 200 से ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पंजाब की सरकार ने यहां पर कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है, मंत्री जी ने स्वयं भी यहां पर यह बात बोली थी। पंजाब कृषि प्रधान राज्य है। पंजाब का किसान अपने बच्चों से भी ज्यादा अपनी फसल को प्यार करता है और आज पंजाब की हालत यह है कि जहां हिन्दुस्तान के बाकी हिस्सों में बाढ़ आई, बहुत ज्यादा बारिश हुई, लेकिन वहां पर सामान्य से भी कम बारिश हुई है। कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर 75% कम बारिश हुई, कई जिलों में 54% कम हुई और कई में 25% कम हुई। इस तरह जो ऐवरेज रेनफॉल है, वह बहुत कम हुआ है।

पंजाब की दूसरी सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, वहां पर बिजली का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। पंजाब सरकार ने पिछले साढ़े चार सालों में बिजली का कोई भी नया प्लांट नहीं लगाया है। हर साल वहां पर 15% बिजली शॉर्ट होती है, लेकिन इसे बढ़ाया नहीं गया है। हालत यह है कि पंजाब की 80% इरिगेशन ट्यूबवैल से हुआ करती है और बिजली

न होने के कारण वहां के किसान डीज़ल से अपने जैनरेटर सैटों अथवा पम्पिंग सैटों को चला रहा है, जिससे उनकी लागत बहुत अधिक बढ़ गई है।

पंजाब में एक बड़ी समस्या और भी है कि वहां पर जो शैलो ट्यूबवैल थे, वे सब सूख गए हैं। वॉटर लैवल बहुत डाउन हो चुका है और वॉटर लैवल डाउन होने के कारण वहां पर किसानों को बड़े ट्यूबवैल लगाने की जरूरत पड़ रही है। पहले जो ऊपर वाले ट्यूबवैल लगाए जाते थे, उनका खर्च 20,000 से 25,000 रुपये तक आता था। अब पंजाब में एक ट्यूववैल लगाने का खर्चा डेढ़ लाख, दो लाख के करीब आता है। इसलिए उसकी यह कॉस्ट भी बढ़ गई है और इस साल किसानों को दो हजार से तीन हजार प्रति एकड़ पर ज्यादा अपनी पैड़ी को बचाने के लिए खर्चा करना पड़ रहा है। इस वक्त जो धान की कीमत एनाउंस की गई है उसमें जो एम0एस0पी0 में इंक्रीज किया है, वह सिर्फ दस रुपए है। यह किसानों के साथ खिलवाड़ किया गया है। पंजाब में जिस तरह सूखा पड़ रहा है तो उसमें सौ रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की जरूरत है। पंजाब में पहले भी जो गेहूं की बात हुई, उसमें भी पचास रुपए जो बोनस प्रति क्विंटल पर दिया गया, वह ज्यादा किसानों को नहीं मिल सका, क्योंकि जो गेहूं किसान बाजार में लाया, प्राइवेट खरीदारों ने उसे खरीद लिया, जिसमें एम0एस0पी0 से दस-बीस रुपए ज्यादा दिया। होना यह चाहिए था कि अगर उसको बीस रुपए, ज्यादा दिए हैं तो कम से कम जो तीस रुपए बैठते थे तो वह दे देते जिससे किसान की यह हालत नहीं होती। पंजाब की एक और बदकिस्मती है कि जब भी एसेसमेंट करने को कमेटी जाती है, सर्वे करने जाते हैं तो वहां सूखा है या नहीं, केवल वहां की हरियाली से अंदाजा लगा लेते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि पंजाब का किसान ज्यादा मेहनत करता है और अपनी फसल को मरने नहीं देता। इसलिए वह डीजल पर भी ज्यादा खर्च करता है, ज्यादा खाद डालता है, ज्यादा मेहनत करता है, तो उसका इस हिसाब से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। पंजाब के किसान का सूखाग्रस्त एरिया डिक्लेयर करना चाहिए कि खेती पर उसकी कितनी कॉस्ट आई है। इसमें उसका कितना डीजल लगा है, कितनी उसकी लेबर बढ़ी है, कितनी उसकी खाद बढ़ी है। इस हिसाब से उसकी कॉस्ट को देखना चाहिए, न कि जो हरियाली है जिसको उसने बचाया है। तो उसने कोई माड़ा काम नहीं किया है, देश का भंडार भरने में पंजाब का बहुत बड़ा योगदान है इसलिए वह मेहनत करते हैं, मेहनत करके उसको बचे या न बचे मगर अपनी फसल पर पूरा खर्चा करते हैं। यही कारण है कि आज पंजाब का किसान जिसको अन्नदाता कहा जाता था, आज पंजाब का किसान खुदकशी कर रहा है और वह कर्ज के भार से दबा पड़ा है, उसको बहुत खतरे की घंटी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी सुसाइड हुए हैं उनका रिकार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब सरकार से मंगवाए। जिस तरह से विदर्भ में पैसे दिए गए उनको कंपन्सेट किया गया, पैकेज दिया गया तथा और स्टेटों में भी दिया जा रहा है और इससे हमें खुशी है कि दूसरे प्रदेश के लोग भी हमारे भाई हैं, लेकिन पंजाब के साथ भी इंसाफ होना चाहिए, उन किसानों को भी वही पैकेज मिलना चाहिए ताकि पंजाब के किसान हिम्मत करें और तगड़े होकर इस देश के भंडार में अपना योगदान कर सकें।

[उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) पीठासीन हुए]

मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि यह बड़े दुख की बात है कि जब फसल तैयार हो जाती है मार्केट में आने के लिए, तब एम0एस0पी0 डिक्लेयर किया जाता है। फसल बोने से

पहले यह रेट डिक्लेयर होने चाहिए कि यह मिनिमम प्राइस है, ताकि किसान को एंक्रेजमेंट हो और वह फसल बीज सके। लेकिन होता उल्टा है। तो मैं चाहूंगा कि अब गेहूं की फसल बोने का टाइम है। बाहर से मंगाने पर हमको बारह सौ रुपए प्रति क्विंटल गेहूं यहां पड़ा है। हिन्दुस्तान के किसान को हमने साढ़े छः सौ दिया और ज्यादा से ज्यादा उसको पचास रुपए बोनस दे दिया। अब अगर एम0एस0पी0 डिक्लेयर करें, उससे पहले डिक्लेयर करें, कम से कम आठ सौ रुपया करें, तो मैं नहीं समझता कि हिन्दुस्तान के भंडार में कोई कमी आएगी और बाहर से हमें कोई गेहूं मंगवाने की जरूरत पड़ेगी। पंजाब का, देश का जो किसान है, वह घाटे में चल रहा है, उसको मार पड़ रही है और वह सुसाइड कर रहा है। तो उसको बचाने के लिए सरकार का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। जो अन्नदाता है वह सुसाइड करे, इससे बुरी बात हमारे लिए कोई हो नहीं सकती। महोदय, सरकार से मैं यही विनती करता हूं कि यह जो कमियां हैं..... जिसके कारण आज आत्महत्याएं हो रही हैं, जिसके कारण किसानों की बुरी हालत हो रही है। ..(समय की घंटी).. उनको यह देखना चाहिए, खासकर के मैं पंजाब के बारे में फिर कहूंगा कि इसको सूखाग्रस्त डिक्लेयर करना चाहिए, नहीं तो पंजाब में किसानों को बहुत दुखों का सामना करना पड़ेगा, यह हमें नजर आ रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय। किसानों की आत्महत्या पर कल से अल्पकालिक चर्चा चल रही है। माननीय कृषि मंत्री जी, जो कि देश के एक दिग्गज नेता हैं, बहुत बड़े कद्दावर और काबिल नेता हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं कि अत्यंत धैर्य से, धीरज से वह इस डिबेट को सुन रहे हैं। महोदय, पहले से आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के विदर्भ हिस्से में किसानों द्वारा आत्महत्याएं हो रही हैं। अब ऐसा पंजाब में हो रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। जैसे कि बाजवा साहब ने कहा कि पंजाब एक समय अन्नदाता कहलाता था, गेहूं और धान के उत्पादन में उसका बहुत अधिक योगदान था, लेकिन आज उसका किसान भी आत्महत्या कर रहा है। महोदय, 1980 के दशक को, मैं थोड़ा आपसे समय ले लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : आपको पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोलना है।

श्री रुद्रनारायण पाणि : महोदय, 1980 के दशक में दुर्भाग्य से पंजाब के आसपास इस देश में उग्रवाद चल रहा था और उस समय समाचार पत्रों में बहुत कम दिन यह सुनने में आता था, No killing in Punjab today. उस समय के उग्रवाद के कारण डेली हत्या होती थी, प्रतिदिन किलिंग होती थी, No killing in Punjab today because of insurgency and all that. उसी प्रकार से आज देश के छह-सात राज्यों में देश के किसानों द्वारा आत्म- हत्याएं हो रही हैं, जिस प्रकार से आत्महत्याएं हो रही हैं, उसके कारण शायद पत्रकार एक दिन भी लिख नहीं सकेगा, no farmer committed suicide today. कल हमारे एक वक्ता बोल रहे थे कि बहुत कम समय के अंतराल में दुर्भाग्य से एक-एक किसान आत्महत्या करता है। यह हम सबके लिए गंभीर विषय है और हम सब को इसके बारे में मिलकर सोचना चाहिए। इस समस्या पर मैं आपको क्रिटिसाइज करूं, आप मुझे क्रिटिसाइज करें, एनडीए क्रिटिसाइज करेगा यूपीए को

और यूपीए क्रिटिसाइज करेगा एनडीए को, यह क्रिटिसाइज करने का विषय नहीं है, यह विषय politicisation का विषय नहीं है, no criticism, no politicisation.

महोदय, मैं इस सदन से निवेदन करता हूं कि जब सत्र आता है, जब अधिवेशन होता है, हम एक रूटीन जैसा कर देते हैं, जैसे रेलवे का एप्रोप्रिएशन बिल आता है, जैसे जनरल बजट का एप्रोप्रिएशन बिल आता है, उसी प्रकार महंगाई के बारे में हर सत्र में एक चर्चा कर लेते हैं, उसी प्रकार से किसानों की आत्महत्या के बारे में एक बार चर्चा कर लेंगे, यह दुर्भाग्य का विषय होगा। हम सब लोगों को यहां प्रण करना चाहिए कि अगले सत्र में हम इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, वह इसलिए नहीं करेंगे कि तब तक किसानों द्वारा कोई आत्महत्या नहीं होनी चाहिए। हम सब को मिलकर इसको रोकना चाहिए।

महोदय, हमारे कृषि मंत्री जी सहकारिता विभाग भी देखते हैं। अगर सहकारिता को ढंग से चलाया जाएगा, तो उससे किसानों को भी लाभ मिल सकता है। एनसीयूआई एक प्रोजेक्ट है जो कि सहकारिता विकास के लिए लोगों को शिक्षा देता है। मैंने मंत्री महोदय को इस सिलसिले में उड़ीसा का एक केस दिया है। मैं राजनीति से ऊपर उठकर यह कहूंगा कि यदि यह योजना बंद होगी, तो उससे सहकारिता अफेक्टिड होगी और फारमर्स भी अफेक्टिड होंगे। मैंने इस संबंध में मंत्री जी को ज्ञापन दिया है। मैं राजनीति से ऊपर उठकर कह सकता हूं, वहां के लोग मेरे पास आए थे, उन लोगों ने मुझे यह भी बोला कि श्री वर्धन साहब के साथ वे लोग मंत्री महोदय से मिले थे और ज्ञापन दिया था। मैं भाजपा का हूं और श्री वर्धन भाकपा के हैं। इसमें भाजपा और भाकपा का कोई भेद नहीं रहता है। वे लोग मुझसे बोले कि वे श्री वर्धन साहब के साथ श्री शरद पवार के पास मिलने के लिए गए थे।

मैंने कहा कि मैं भी आपके इस ईशू को उठाउंगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अनुरोध करूंगा कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने ज्ञापन दिया है, कृपया उसके प्रति ध्यान देंगे।

(श्री सभापति पीठासीन हुए)

सहकारिता के विकास के लिए वह कार्यक्रम बनता है। महोदय, हमारी पार्टी ने सन् 2005 में मुझे आंध्रप्रदेश भेजा था। किसानों की आत्महत्या के बारे में हमारी पार्टी की ओर से एक डेलीगेशन वहां अध्ययन हेतु गया था। 2005 में इस विषय के ऊपर जब हमने चर्चा की थी, उस समय भी मैंने इसी विषय को उठाया था। बार-बार इसीलिए उठाया जाना चाहिए ताकि इसके ऊपर सरकार की ओर से ध्यान दिया जाए।...(**समय की घंटी**)...। महोदय, Cotton Corporation of India, सीसीआई का यह विषय है। आन्ध्र का गरीब, कपास उगाने वाला किसान कपास लेकर सीसीआई के सामने जाता है, आशा करके जाता है कि जब वह उसे बेचेगा तो उसे सही रेट मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा। लेकिन सीसीआई के लोग वहां कहते हैं कि तुम्हारी कपास की क्वालिटी सही नहीं है, इसे वापस ले जाओ, हम नहीं खरीदेंगे। वह निराश होकर सीसीआई के गेट के सामने किसी बिचौलिए को बेच देता है और एक दिन के अंदर जब वह ट्रेक्टर लेकर वापस जाता है, तब वह बिचौलिया उसी माल को, उसी कपास को हाई रेट पर, सीसीआई के शेडयूल्ड रेट पर उनको दे देता है। वही कपास कम रेट पर किसान द्वारा बिचौलिए को दिया जाता है, एक दिन के बाद, 24 घंटे के अंदर बिचौलिया सीसीआई में जाकर उसी कपास को बेचता है और

गरीब किसान पैसा न मिलने के कारण खुदखुशी कर लेता है। सभापति महोदय, इस बीच आप आ गए हैं, इसलिए मैं इस विषय को कोई politicise नहीं करूंगा, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूंगा। हमारे सभापति के नेतृत्व में हमारी राज्य सभा चलती है। आपने मौका दिया कि इस विषय पर गंभीरता के साथ सोचें कि कैसे अगले सत्र में किसानों की आत्महत्या के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे और वह इसलिए नहीं करेंगे कि तब तक किसानों की आत्महत्याओं पर हम पूर्ण रूप से नियंत्रण कर पाएंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आप सबका धन्यवाद।

कृषि मंत्री (श्री शरद पवार) : मान्यवर, पिछले दो सालों से देश में और इस सदन में ...(व्यवधान)...

– **श्री सभापति** : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रश्न खेती के संबंध में या किसानों के संबंध में सभी पार्टियों के लोगों ने खूब ज्यादा उठाए हैं। मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि हाउस में उपस्थिति अच्छी हो तो ठीक है। कांग्रेस पार्टी से मैं खास तौर से यह निवेदन करूंगा।

श्री शरद पवार : तीसरी बार इस विषय पर इस सदन में गंभीरता से चर्चा हो रही है। मैंने इससे पहले एक बार सदन में कहा था कि आत्महत्या की समस्या इस देश में अभी शुरू हो गयी है, ऐसी बात नहीं है। मैंने हर राज्य की पिछले पच्चीस-तीस सालों से जो स्थिति है, इसके आंकड़े सदन के सामने दिए थे। मैंने इस सदन में इससे पहले भी कहा था कि हमारे देश में हर पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो उसका रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी उस पुलिस स्टेशन की होती है। यह रिकॉर्ड एक साल के बाद एक किताब के रूप में भारत सरकार का गृह मंत्रालय प्रस्तुत करता है, पब्लिश करता है। 1995 तक हर प्रान्त की इनफॉर्मेशन पब्लिश होती थी, लेकिन इसमें से किसान परिवारों से कितने लोग हैं, इस प्रकार की अलग से इनफॉर्मेशन इसमें कभी नहीं आती थी। 1995 में भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया कि इसमें किसान परिवार के लोग कितने हैं, कौन से पुलिस स्टेशन में हैं, कौन सी तहसील में हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं, कौन से राज्य में हैं...।

इसकी अलग information collect करके देने का प्रबंध कीजिए, तब से, 1995 से आज तक, किसान परिवार के कितने लोग हैं, इसकी information अलग से प्रकाशित होती है। मोटे तौर पर यह बात सामने आ गई है कि हर साल हिंदुस्तान में एक लाख के करीब लोग आत्महत्या करते हैं और इन एक लाख आत्महत्या करने वाले लोगों में 14 से 16 प्रतिशत लोग किसान परिवार के होते हैं। 1995 से आज तक, सभी सालों के आंकड़े देखने के बाद, इसमें 14 या 16 परसेंट किसान परिवार के लोग आत्महत्या करते हैं, यह बात साबित हो गई है, यह सामने आ गई है। देश के सभी राज्यों में आत्महत्या के कुछ न कुछ incidences होते हैं, मगर पिछले दो सालों में यह समस्या सबके सामने ज्यादा आ गई, क्योंकि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का विदर्भ का एक इलाका, केरल का वायनाड, पालघाट, कासरगोट, इडक्की, ये तीन-चार जिले, आंध्र के 16 जिले और कर्नाटक के 6 जिले, इनमें देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या के केसेज हो गए हैं, जिसका reaction इस सदन में हुआ है और इस बारे में इस सदन में बहुत गंभीरता से चर्चा हुई।

प्रथम, आपको याद होगा, कि इसके रूट कॉज़ में जाने के लिए हमने कोशिश की। आंध्र राज्य में, जहां आत्महत्याएं हुईं, इन सभी परिवारों के घरों में जाकर, वहां की स्थिति क्या

है, वह आत्महत्या करने के लिए क्यों तैयार हुआ, इस तरह से information collect करने का प्रयास किया। वैसा ही काम महाराष्ट्र में हुआ, वैसा ही बाकी राज्यों में भी हुआ। इसमें कई बातें हैं - कभी फसल खराब हुई होगी, सूखे की समस्या होगी, उचित मूल्य नहीं मिले होंगे, डीफॉल्टर होने के बाद प्राइवेट मनी लेंडर के पास गए होंगे, वहां पच्चीस प्रतिशत से साठ प्रतिशत सूद देने का संकट उनके सामने आ गया, वह देने की ताक़त नहीं रही, जो क्रॉप लोन के लिए पैसा लिया, उसी समय घर में कोई बीमारी आ गई, उसी समय किसी लड़की की शादी करने की समस्या सामने आ गई या उसी समय परिवार में किसी की ऐजुकेशन के लिए कुछ खर्चा करने की आवश्यकता पड़ी, तो जो क्रॉप लोन के लिए पैसे लिए थे, वे divert करने पड़े। दूसरे साल फसल ठीक से नहीं आई, तो क्रॉप लोन के पैसे वापस नहीं कर सका और डीफॉल्टर बन गया, डीफॉल्टर बनने के बाद प्राइवेट मनी लेंडर के पास गया और भारी सूद से उनसे पैसे लिए - इस तरह से अलग-अलग केसेज़ के रिज़ल्ट, यह सब जांच करने के बाद राज्य सरकार और भारत सरकार के सामने आए।

एक समस्या और सामने आ रही है कि देश के कई राज्यों में दिन-ब-दिन ग्राउंड का जो वाटर लेवल है, वह नीचे जा रहा है और मुझे सबसे ज्यादा चिंता है पंजाब और हरियाणा की। पंजाब और हरियाणा के लिए कई सदस्यों ने यहां कहा कि देश का अनाज का भंडार मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा योगदान इन राज्यों ने दिया है, मगर पिछले कई सालों से जिस तरह का क्रॉप लोन की एक परंपरा वहां शुरू हुई, इसके परिणाम में वहां का वाटर लेवल दिन-ब-दिन नीचे जा रहा है और इस बारे में पंजाब सरकार, हरियाणा गवर्नमेंट और भारत सरकार, तीनों ने मिलकर कुछ कदम नहीं उठाए तो शायद पांच-दस साल के बाद, मुझे मालूम नहीं, इस देश की अनाज की समस्या कितनी गंभीर होगी !

इसलिए आत्महत्या एक समस्या है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए, यह बात भी सदन के सामने आई है। यदि ठीक तरह से देखा जाए तो पूरे कृषि क्षेत्र की ओर गंभीरता से ध्यान देने की परिस्थिति आज पैदा हो गई है। देश के कृषि क्षेत्र की आज क्या स्थिति है? आज दुनिया की 16 प्रतिशत आबादी हिंदुस्तान में है, दुनिया का 4.52 परसेंट पानी हिंदुस्तान में है और दुनिया की 2.4 परसेंट जमीन हिंदुस्तान में है। आज हिंदुस्तान की 56 परसेंट से ज्यादा आबादी खेती करती है और देश के राष्ट्रीय उत्पाद में 21 प्रतिशत के contribution की जिम्मेदारी कृषि क्षेत्र की है और देश के एक्सपोर्ट में 11 परसेंट के contribution की जिम्मेदारी कृषि क्षेत्र के माध्यम से पूरी होती है। पिछले 3-4 सालों के आंकड़े देखने के बाद, मैं कह सकता हूं कि 208 मिलियन टन के आसपास अनाज इस देश में पैदा होता है। देश में कृषि क्षेत्र से जो उत्पादन होता है, यदि इसकी कीमत देखें तो 517 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन, इस देश के किसान परिवार करते हैं, लेकिन आज इतना बड़ा काम करने के बाद भी यह क्षेत्र संकट में घिर गया है। इस बारे में हमें बड़ी गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, यह स्थिति क्यों हो गई है, कब से हो गई है, इस ओर भी हमें देखने की आवश्यकता है। हम इस तथ्य को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि जब हम आज़ाद हुए थे, उस समय हिंदुस्तान की आबादी 35 करोड़ थी और 35 करोड़ में से 80 प्रतिशत लोग खेती के क्षेत्र में काम करते थे, लेकिन आज हिंदुस्तान की आबादी 106 करोड़ के लगभग है और इनमें से 56 से 60 प्रतिशत लोग ही खेती करते हैं। यानी जमीन पर बोझ ढाई परसेंट से ज्यादा बढ़

गया है, ज़मीन नहीं बढ़ी है। कल इसी सदन में चर्चा हुई कि उद्योगों के लिए कई राज्यों में नए क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। चाहे नया उद्योग लगाना हो, चाहे National Highways बनाने हों, चाहे छोटे रास्ते बनाने हों, चाहे गांवों में स्कूल बनाने हों, चाहे दिल्ली का जो विस्तार हम आस-पास देख रहे हैं, इस देश में हर शहर का विस्तार हो रहा है, लेकिन सभी जगहों पर agricultural land ही non-agricultural sector में जाती है और urbanisation के काम में जाती है। इस प्रकार जमीन कम हो रही है और जमीन पर बोझ बढ़ रहा है। पहले जो 25 करोड़ में से 80 परसेंट लोग कृषि पर आधारित थे, आज 106 करोड़ में से 60 परसेंट लोग कृषि पर आधारित हैं, इतना बड़ा बोझ आज जमीन पर है।

सभापति जी, इस सदन में कई बार चर्चा हुई, कई साथियों ने यह कहा कि भूमि-सुधार के बारे में कोशिश करने की आवश्यकता है। पिछले कई सालों में कई राज्यों ने भूमि-सुधार के बारे में कदम उठाए हैं। कई राज्यों की परिस्थिति ठीक रही है, यह बात भी साफ है, मगर हम कहां तक पहुंचे हैं? कितने बड़े पैमाने पर fragmentation हुआ है? आज किसान परिवार के पास जमीन कितनी है - 2 या 4 एकड़ जमीन जिस किसान के पास है, उसे अपना परिवार चलाने की जो आवश्यकता है, वह ताकत उसके पास नहीं रही है। यहां सदन में जो कहा गया, यह बात सच है कि National Sample Survey के माध्यम से इस देश में किसान परिवारों का जो survey किया गया, इनमें से 40 प्रतिशत किसानों ने यह कहा कि हम खेती को छोड़ना चाहते हैं। वे खेती छोड़ना चाहते हैं क्योंकि आज खेती करना economic नहीं रहा है। आज holding बहुत सीमित हो रही है और फिर भी हम यह holding कम करने के लिए कुछ न कुछ सुझाव देते हैं, मुझे लगता है कि इससे किसान परिवार का और entire agricultural sector का बड़ा नुकसान होने वाला है।

आप हर गाँव में जाइए, जिस किसान परिवार में जितने सदस्य हैं, इनमें से एक सदस्य खेती करता होगा और दूसरा सदस्य कहीं गवर्नमेंट सर्विस करता होगा या किसी कंपनी में सर्विस करता होगा, तो उस परिवार का मकान, उसका रहन-सहन एक तरह से अच्छा है, यह हमें देखने में मिलता है। मगर जिस परिवार में केवल खेती ही करते हैं, उनके लैंड का आप रेकार्ड देखिए, उसमें लिखने के लिए जगह नहीं होती है - इस बैंक से पैसा लिया है, इस लैंड डेवलपमेंट से पैसा लिया है, इस सोसायटी से पैसा लिया है, जहाँ से पैसा मिल सकता है, वहाँ से पैसा लेने की कोशिश करते हैं और वह बिल्कुल कर्जदार होता है। खेती के साथ-साथ सप्लीमेंटरी इन्कम देने के लिए हमें मजबूती से कदम उठाने होंगे।

सर, आजादी के बाद जब जवाहरलाल नेहरू प्रधान मंत्री थे, तब शुरू के जो कुछ प्लांस बने, इनमें सबसे ज्यादा importance खेती के ऊपर दिया गया था। यह बात सच है कि पंडित जी ने उस समय कहा था कि everything can wait, but not agriculture, जिसका जिक्र कल सदन में किसी सदस्य ने किया था, यह बात सच है। पूरा इतिहास देखने के बाद, जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधान मंत्री थे, तो सबसे ज्यादा ध्यान खेती के ऊपर दिया गया, इस देश में कई इरिगेशन प्रोजेक्ट्स तैयार करने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दे दिया। आज डा. बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में हमेशा बात होती है कि इस देश के संविधान को तैयार करने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, यह बात सच है। मगर कई देशवासियों को यह मालूम नहीं कि इस देश के इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान डा. बाबा साहब अम्बेडकर ने तब दिया था, जब वे इस देश के वॉटर रिसॉर्सेज़ मिनिस्टर थे। भाखड़ा नांगल हो या दामोदर वैली प्रोजेक्ट हो या इस देश के जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वॉटर

2.00 P.M.

रिसॉर्सेज़ मिनिस्टर के रूप में डा. बाबा साहब के पास इसकी जिम्मेदारी थी, तब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तब उन्होंने एक निर्णय लिया था कि जब तक बिजली का उत्पादन ज्यादा नहीं होता और गाँव तक नहीं होता और हर राज्यों में इनका ग्रिड नहीं बनेगा, तब तक गाँव में बिजली जाने की परिस्थिति तैयार नहीं होगी। जब तक पानी और बिजली, ये दो चीज़ें हम गाँव में नहीं देंगे, तब तक इस देश की खेती का उत्पादन नहीं बढ़ेगा और फूड सिक्योरिटी की समस्या को हल करने में हम कामयाब नहीं होंगे। इस तरह का निर्णय उस समय डा. बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया था। जवाहरलाल नेहरू जी के योगदान के बाद जब इस देश की जिम्मेदारी श्रीमती इन्दिरा गाँधी के ऊपर पड़ी थी, तब इस देश में ग्रीन रिवोल्युशन की नींव सच्ची तरह से खड़ी की गई थी। मुझे याद है कि सी. सुब्रह्मण्यम इस देश के कृषि मंत्री थे और इस देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर सेक्टर में लाकर जब तक हम कुछ कदम नहीं उठाएंगे, तब तक फूड सिक्योरिटी की समस्या दूर नहीं हो पाएगी, यह बात पहली बार उन्होंने रखी थी। बाबू जगजीवन राम और सी. सुब्रह्मण्यम के इस क्षेत्र में contribution को हम कभी भुला नहीं सकते।

सर, कल इस सदन में सीड्स के बारे में बात हुई थी। दो दिन पहले मुझे एक किताब भेजी गई, इस दुनिया में जिन्हें नोबल प्राइज़ मिला है, कृषि के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया, ऐसे एक ही व्यक्ति हैं, जिनका नाम नॉर्मन बोरलॉग है। डॉ. बोरलॉग भारत में हमेशा आते हैं। आज शायद उनकी उम्र 90 से ऊपर है। 3-4 महीने पहले यहाँ आए थे, हम सब लोगों से उन्होंने बड़ी गम्भीरता से बात भी की थी। आज पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी ने 1966-67 में गेहूँ के क्षेत्र में जो क्रान्ति की, इसका पूरा योगदान डॉ. बोरलॉग का है। उन्होंने एक मेक्सिकन वैरायटी तैयार की थी और सी. सुब्रह्मण्यम साहब ने एक decision लिया कि वे मेक्सिकन वैरायटी देश में लाकर इसका प्रचार करें। एक शिप लोड मैटेरियल उन्होंने वहाँ से मंगाया। यहाँ आने के बाद उन्होंने देश के सभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स और एग्रीकल्चर कमिश्नर्स की मीटिंग बुलाई।

और सभी राज्यों को उन्होंने यह सुझाव दिया कि यह नया सीड हम आप को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पंजाब के सिवाय एक भी राज्य वह सीड लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। उस समय के एग्रीकल्चर कमिश्नर, गिल साहब इस बारे में मुझ से ज्यादा बता सकेंगे, शायद ग्रेवाल उन का नाम था और उन की पत्नी श्रीमती सरला ग्रेवाल राजीव गांधी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी थीं। उन्होंने यह जिम्मेदारी लेने की तैयारी की और यह पूरा मैक्सिकन सीड पंजाब गया और एक साल में पंजाब में गेहूं की इतनी पैदावार हुई कि गेहूं रखने के लिए जगह नहीं थी। गोदामों में और स्कूल की बिल्डिंग्स में जहां-जहां जगह थी, वहां गेहूं रखा। देश को जो break through मिला, वह इस माध्यम से मिला। मैं इस सदन में यह उदाहरण इसलिए रखना चाहता हूं कि हम लोगों ने ट्रेडीशनल सीड्स की बात की, उस की उपयोगिता है। इस देश में बहुत से ट्रेडीशनल सीड्स अच्छे हैं, उन का इस्तेमाल करना चाहिए और उस में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर इन सभी क्षेत्रों में दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, उसे नजरंदाज करने से हम लोगों को लाभ नहीं होगा। यह बात सच है, मगर हमें यह देखना होगा और मुझे खुशी है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, मेरे सहयोगी भी यहां हैं, पिछले कई सालों से टोटल इनवेस्टमेंट जो कृषि क्षेत्र में हो रहा है, उस में परिस्थिति

कोई अच्छी है, ऐसा कहने की स्थिति आज नहीं है। प्लानिंग कमीशन ने इस बारे में कदम उठाए हैं।

श्री सभापति : इस में फाइनेंस मिनिस्टर का सहयोग नहीं मिल रहा है क्या?

श्री शरद पवार : नहीं, उन का अच्छा सहयोग मिल रहा है। ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। Infact ये दो सालों में इस क्षेत्र में जो कुछ कंट्रीब्युशन हुआ, उस में फाइनेंस मिनिस्टर का सहयोग इतना नहीं होता तो इतना हो नहीं सकता था। मैं इस बारे में आगे जरूर बताऊंगा। In 1980-85, that is, during the Sixth Plan, the All India situation indicates that the gross fixed capital formation in agriculture, as proportion to the GDP, has declined from 3.1 per cent to 1.6 per cent during the year 1997-02, that is, essentially, the Ninth Plan. तो यह स्थिति कहां से शुरू हुई, कब शुरू हुई, यह बताने के लिए मैंने deliberately सदन के सामने यह जानकारी दी। Investment in agriculture, as percentage share of the GDP, at current prices, decreased from 2.56 per cent to 1.6 per cent during this particular period, that is, from 1999-2004. जहां 56 परसेंट पॉपुलेशन इनवॉल्व्ड है, पूरे देश की फूड सेक्युरिटी की समस्या जिन के ऊपर निर्भर है, इस क्षेत्र में हम सब लोगों ने मिलकर पिछले कई सालों से किस तरह से कदम उठाया है, इस का नक्शा इस माध्यम से आज हमारे सामने आया है। महोदय, मुझे इस से भी ज्यादा गंभीर बात यह लगती है कि share of public investment has come down like anything.

महोदय, आज एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर की इनवेस्टमेंट होती है, वह इनवेस्टमेंट किस की है? चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या दूसरा सेक्टर हो - इन सभी सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर का इनवेस्टमेंट आता है। कई इंडस्ट्रियल हाउसेज इस में इनवेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, कई जगहों पर मल्टीनेशनल्स भी आए होंगे और कोई एंटरप्रिन्युअर आया होगा, मगर एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की जो इनवेस्टमेंट आई है, इस में से 90 प्रतिशत इनवेस्टमेंट इस देश के किसानों की है।

आज चाहे किसी को ट्यूबवेल लगाना हो, ट्रैक्टर लेना हो, पाईपलाइन लगवानी हो, इलेक्ट्रिसिटी की मोटर लगानी हो, यह सब इन्वेस्टमेंट आज किसान किसी बैंक के पास से या और किस माध्यम से, पैसा उन्हें लेने का जो रास्ता खुला है, इसका आधार लेता है और वह burden अपने सिर पर लेता है। वह burden अपने सिर पर लेकर, यह पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर, वह वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है। इस माध्यम से पैसे आज प्राइवेट सेक्टर के इस क्षेत्र में आया है। आज जरूरत यह है कि इसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं और हम इस क्षेत्र में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस तरह ला सकते हैं, इस बारे में मिल-बैठ कर सोचने की जरूरत है और उस तरह से कदम उठाने की जरूरत है। Agriculture, as per the Constitution, is a State subject. यह स्टेट का सब्जैक्ट है, पर इससे हम अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज करना नहीं चाहते। मगर यह समय भी आ गया है कि इस सदन में बैठे हुए सभी सदस्यों की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की हुकूमत कहीं-न-कहीं तो है। यह सोचने की स्थिति पैदा हुई है कि हर राज्य में, सभी क्षेत्रों में आज कितना प्रोविजन हम लोग करते हैं और इस क्षेत्र में हम कितना ध्यान देते हैं। इस पर हम ठीक तरह से देखेंगे नहीं, तो इसकी जबरदस्त कीमत शायद इस देश

को अगले कुछ सालों में देनी पड़ेगी। 8 से 10 परसेंट का ग्रोथ रेट इस देश में होना चाहिए, यह बात हमने बार-बार कही है। यदि हमें 8 से 10 परसेंट की ग्रोथ रेट एचीव करनी है, तो एग्रिकल्चर सेक्टर का योगदान, इसका ग्रोथ रेट 4 परसेंट के आस पास होने की आवश्यकता है। यदि हमें एग्रिकल्चर की ग्रोथ 4 परसेंट चाहिए तो, इसमें investment in agriculture sector will require ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति : आज कितनी है?

श्री शरद पवार : इस साल जो है, this is one of the good years and we have reached 3.2 - 3.3 per cent ...*(Interruptions)*...

SHRI VIKRAM VERMA (Madhya Pradesh) : No, Sir, it is less than 2 per cent...*(Interruptions)*...

श्री सभापति : नहीं है, नहीं है ...**(व्यवधान)**...

SHRI SHARAD PAWAR: In the last two years, it was ...*(Interruptions)*...

श्री विक्रम वर्मा : इस साल की तो अभी आई नहीं है। ...**(व्यवधान)**... पिछले बजट में आपने बताया था कि it is less than 2 percent. ...*(Interruptions)*...

SHRI SHARAD PAWAR: No, that is not correct. ...*(Interruptions)*... In fact ...*(Interruptions)*... आप सुनिए न ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : ठीक है, हो गया ...**(व्यवधान)**...इसीलिए मैंने पूछा था ...**(व्यवधान)**...

SHRI SHARAD PAWAR: In fact, year before last year, it was up to 1.9 per cent, but this is the first year in agriculture that includes fishery, that includes animal husbandry, all together, we have crossed 3 per cent. This is the first year we have reached this particular level. But if we have to attain 4 per cent and if we have to continue that growth rate-- between 8 - 10 per cent - then, that will require, at least, 14 -15 per cent investment in agriculture sector, which will be somewhat near to Rs.5 lakh crores, which is a quite huge responsibility.

खेती का टोटल क्षेत्र देखने के बाद यह परिस्थिति भी हमारे सामने आई है कि आज 60 प्रतिशत जमीन पर खेती नेचर के भरोसे रहती है और 40 प्रतिशत में हमारे पास इरिगेशन है। आज जब तक हम small, medium & major irrigation projects and watershed development पर राज्यों में सही तरह से ध्यान नहीं देंगे, तब तक मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में बदलाव नहीं आएगा। इतने बड़े पैमाने पर कई जगह पर - Recently, there was one meeting wherein myself, the Finance Minister and some of our other colleagues were discussing on this issue. There are a number of

projects which were taken in hand by many State Governments, which are under construction for the last 20 years, 30 years. The total cost of the project which was somewhat near to Rs.20 crores, that has gone to Rs.200 crores today; and, still it is not completed.

हम लोगों की एक आदत है कि डेमोक्रेसी में हमें सब लोगों को खुश रखना पड़ता है। इसीलिए हमारी काबिलियत क्या है, यह बिना देखे हर क्षेत्र में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स लेना, हर जिले में प्रोजेक्ट्स लेना और सालों-साल उन प्रोजेक्ट्स का पूरा नहीं होना, ऐसी परिस्थिति आती है। इसकी टोटल कॉस्ट इतने बड़े पैमाने पर आती है, लेकिन उसका फायदा न तो खेती को मिलता है और न ही हम वह प्रोजेक्ट समय पर पूरा कर पाते हैं।

आज इस देश में 232 major projects, 922 medium projects and the number of old projects which will require some repair is about 87. आज इस देश में 1248 projects अधूरे हैं, जो कई सालों से हम पूरे नहीं कर सके हैं। मैंने हर राज्य सरकार को लिखा है, I have written to all the Chief Ministers that they should look into it. They should pay a little more attention to it; and they should try to concentrate on it and complete these projects on time. They should give a lot of priority to the agriculture sector.

सभापति जी, जैसे पानी की समस्या हमारे सामने आई है, ऐसे ही कुछ और समस्या हमारे सामने आ रही है। वह समस्या यह है कि हमारी जमीन की उत्पादन-शक्ति, प्रोडक्टिविटी, वह दिन-ब-दिन कम हो रही है। जमीन में जो माइक्रोन्यूट्रीएंस रहते हैं, उसकी कमी आ रही है और जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, उसका जब हमने दुनिया के साथ कंपेयरेजन किया, तो आज भी हमारे यहां कैमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है, मगर इसका जो बेलेन्स यूज करना चाहिए, यह बेलेन्स यूज में बहुत पीछे है। इससे हमारी जमीन का भी नुकसान हो रहा है।

जैसा निर्मला जी ने यहां कहा था कि ऑर्गेनिक मैथ्ड्स पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, जरूर इसकी उपयुक्तता है। जमीन की टेक्सचर इम्प्रूव करने के लिए इससे मदद होगी और इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। चाहे वर्मीकल्चर हो, चाहे ऑर्गेनिक मेटेरियल हो, जो-जो मांग खेती में है या जिसकी उपयुक्तता नहीं है, इसका आधार लेकर सलाह कर हम फिर जमीन में भेजेंगे, तो शायद इससे जमीन के टेक्सचर में सुधार हो। इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद हो सकती है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज इस बारे में लोगों में एक कैम्पेन करने के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम राज्य सरकार को कांफीडेन्स में लेकर हम लोगों ने किया है।

महोदय, जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यह कुछ करने की आवश्यकता है, वैसे ही अच्छी तरह से वैरायटी डवलप करने के लिए भी ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस देश में आज इंडियन कौंसिल फोर एग्रीकल्चर रिसर्च, एक बहुत बड़ी संस्था खड़ी हुई है। इसमें 6000 साइंटिस्ट काम करते हैं। हमारे पास क्रोप-वाइस साइंटिस्ट हैं, फसलवार साइंटिस्ट हमारे पास हैं। पिछले दो साल में 240 से ज्यादा नई वैरायटी इन लोगों ने डवलप की है। इन वैरायटी का प्रसार करने के लिए चाहे कृषि विज्ञान केन्द्र हो या स्टेट्स का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का

एक्सटेंशन विंग हो, उनके माध्यम से कुछ न कुछ कदम उठाए गए हैं। मुझे यह मालूम है कि स्टेट गवर्नमेंट के एक्सटेंशन विंग की हालत दिन-ब-दिन खराब हो गई है, दुबली हो गई है। भारत सरकार ने इसलिए एक नया कार्यक्रम "आत्मा" नाम का हाथ में लिया है। इसके माध्यम से हर गांव में लोगों की एक टीम तैयार करके, उनको ठीक तरह से जो कोई बदलाव आ रहा है खेती के क्षेत्र में, सीड के क्षेत्र में या जो कोई समस्या आ रही है, एक तरह का मार्गदर्शन देने के लिए एक अच्छा काम देश के 250 डिस्ट्रिक्ट में शुरू करने की एक स्कीम अभी एप्रूव हुई है और इस पर अमल करने का काम आज इस माध्यम से शुरू किया है।

महोदय, यहां उत्पादन बढ़ाने के लिए, नई क्रोप्स लेने के लिए नई सीड्स डवलप करने के लिए बात कही गई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कल यहां थे, उन्होंने कई अच्छे सुझाव दे दिए, मगर उन्होंने एक बात कही ट्रांजेनिक क्रोप के बारे में और थोड़ा-बहुत विरोध करने की उन्होंने बात की थी कि बीटी कॉटन की क्या आवश्यकता है? इस तरह से उन्होंने कहा। यह सच है कि ट्रांजेनिक सीड एक्सपेंसिव होता है, इसके डवलपमेंट के लिए सालों-साल लगते हैं। बीटी कॉटन, जिसका इस्तेमाल कई जगहों पर हुआ है, आज दुनिया में अमरीका जैसा देश हो, मैक्सिको जैसा देश हो, चीन जैसा देश हो, जहां टोटल कॉटन एरिया है, वहां 80-90 परसेंट कवरेज उन्होंने बीटी पर लाया है। बीटी कॉटन से जो डीजीज कॉटन पर आती है, उसको रोकने की ताकत वह जो जीन इसमें डाली है, ट्रांजेनिक जीन, इस मेटेरियल से इस पौधे में उठती है। और इससे प्रोडक्शन बढ़ता है और स्प्रेइंग कम होता है, किसानों का वह खर्चा कम होता है। जहां पानी है, वहां Bt cotton जैसी क्रॉप लेना, जो जमीन इरिगेटिड है, वहां फायदे की बात है और इसका सबसे ज्यादा फायदा गुजरात के किसानों ने लिया। पिछले चार सालों का कॉटन का टोटल प्रोडक्शन प्रति हैक्टेयर यील्ड आप यदि गुजरात का देखें, तो गुजरात में इतने बड़े पैमाने पर किसानों को लाभ हुआ है और इसीलिए गुजरात में कॉटन फारमर की आत्महत्या का कोई केस देखने को नहीं मिलता। पंजाब में पिछले साल तक Bt cotton अलाउड नहीं था, मगर किसी ने सरकार को नहीं पूछा। पंजाब से बाहर के किसान दुनिया से वह सीड वहां लाए, अपने खेत में उत्पादन बढ़ाया, अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत की और इसमें उनको कामयाबी मिली। कई जगहों पर, खास तौर पर आंध्र और विदर्भ में ये शिकायतें आई हैं, जो यहां कल बताई गई थीं। ये शिकायतें क्या थीं? Bt cotton के लिए पानी नहीं हो तो इसमें रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि जो खेत इरिगेटिड नहीं है और मान लीजिए उस साल ठीक तरह से बारिश नहीं आई और उन्होंने Bt seeds का इस्तेमाल किया, तो Bt seed की कीमत ज्यादा होती है और इसलिए किसानों के सिर पर ज्यादा बोझ पड़ता है। इसलिए नान इरिगेटिड क्षेत्र में कहां तक Bt का इस्तेमाल किया जाए, यह सोचने की आवश्यकता है। Bt खराब है, यह जो कहते हैं, यह बात सही नहीं है, Bt से उत्पादन बढ़ा है, यह बात हमारे सामने साफ हुई है।

किसी ने बोला कि भारत सरकार ने Bt को इजाजत दी। मैं यहां कोई राजनीतिक परिस्थिति पैदा नहीं करना चाहता, मगर एक बात जरूर कहना चाहता हूं Bt को इजाजत देने का काम मेरे हाथ से नहीं हुआ। मेरे पास प्रपोज़ल आएगा तो मैं करुंगा, देश के फायदे की बात है, लेकिन मुझे यह कहना है कि जिस दिन मैंने जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय की ली, Bt को रिलीज़ करने का काम मेरे एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनने से पहले हुआ है और फिर जो कुछ हुआ है, वह बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मगर, यह काम करने के बाद, आज

अगर कोई गलत मिसाल आ जाए, तो पूरी टैक्नोलॉजी खराब है, टोटल सीड खराब है, यह कहना ठीक नहीं है। यह बात सच है कि इसकी कीमत कैसे कम हो सकती है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसका लाभ किसानों को जरूर होने वाला है। ...**(व्यवधान)**...

श्री दत्ता मेघे : ज्यादा बोनस दिया नहीं ...**(व्यवधान)**... इसलिए लोगों का बहुत नुकसान हुआ है।

श्री शरद पवार : खराब सीड की एक समस्या देश के सामने है और इस पर रोक लगाने के लिए सीड एक्ट बना है, सीड बिल बना है। मुझे कहते हुए दुख होता है कि यह सीड बिल सदन के सामने पिछले दो सालों से, शिकायत नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी के पास है। ऐसे इम्पोर्टेंट कानून जो होते हैं, जिनका डिले लोगों को बहुत नुकसान कर सकता है, ऐसे ईशू को जल्दी से जल्दी क्लीअर करने की आवश्यकता है। हर जगह से हमेशा शिकायत यही आती है कि हमने नया सीड लिया है, पैसे दिए हैं, मगर यह खराब सीड निकला है, हमारे साथ धोखा हुआ है। इसको रोकने के लिए सीड कानून में बदलाव की आवश्यकता है और बदलाव के लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता थी, वे कदम उठाए गए हैं। आज क्या आवश्यकता दिखाई देती है? आज आवश्यकता यह दिखाई देती है कि कृषि क्षेत्र में हम ज्यादा निवेश कैसे लगा सकते हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट में हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, एग्रीकल्चर क्रेडिट में हम कैसे सुधार कर सकते हैं, सीड्स, फर्टिलाइज़र में हम ठीक कैसे कर सकते हैं, प्रोसैसिंग के बारे में क्या हो सकता है, मार्केटिंग के बारे में क्या

[उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी) पीठासीन हुए]

ध्यान दे सकते हैं, सप्लिमेंट्री इन्कम देने के बारे में क्या कर सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सभी क्षेत्रों में सरकार बदलने के बाद, नई सरकार आने के बाद ज्यादा ध्यान दिया गया है। अभी यहां पर क्रेडिट की बात कही गई थी, इन्फैक्ट इससे पहले फाइनांस मिनिस्टर ने भी यह बात सदन के सामने कही थी। जब देश के सामने पहला बजट था, उस समय उन्होंने यह बात कही थी कि अगले तीन सालों में हम एग्रीकल्चर क्रेडिट को दुगुना बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए हम लोगों ने कदम भी उठाए हैं। मुझे याद है कि उस समय 2003-04 में total institutional credit for agriculture was Rs.86,981 crore, and Rs. 86,981 was the total credit, which was made available to the farmers.

जब यह डिसीज़न लिया गया कि इसे तीन वर्ष में दुगुना किया जाना है, तो 2004-05 में जो टार्गेट बनाया गया, उसके अंतर्गत 1,00,5000 करोड़ तक पहुचने का लक्ष्य रखा गया था। But actual achievement was Rs.1,25,309 crore. पहली बार इतने बड़े पैमाने पर किसानों को ऋण देने का प्रबंध किया गया था और इस पर सौ प्रतिशत से भी अधिक अमल किया गया। In 2005-06, the target fixed was Rs.1,41,000 crore and achievement Rs.1,57,479.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM) : No, it is Rs.1,67,000 crores.

SHRI SHARAD PAWAR: Yes it is Rs.1,67,000 crores, and 111 per cent target was achieved. This is a second achievement of this Government और अभी भी इस क्षेत्र में आगे जाने के लिए हमने पूरी तैयारी की हुई है। सदन के माध्यम से मैं इस देश के किसानों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमें इसमें अवश्य कामयाबी मिलेगी और हमारा सबसे ज्यादा ध्यान इसी पर रहेगा, पिछले दो सालों के परफॉर्मेंस से यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है।

सदन के सामने यह बात रखी गई कि आप उनको पैसे क्यों देते हैं, लोन का बर्डन आप उनके सिर पर देते ही क्यों हैं? देखिए, कैपिटल इन्वैस्टमेंट की आवश्यकता होती है, अच्छे सीड्स की आवश्यकता होती है, फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है साथ ही कल्टिवेशन की जो कॉस्ट आती है, उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है और आज इस देश के किसानों में इतनी ताकत भी नहीं है कि वह अपने स्वयं के इतने रिसोर्सिज़ खड़े कर सकें, जिससे अपने उत्पादन को बढ़ा सकें और इसीलिए उन्हें पैसे दिए जाने की आवश्यकता पड़ती है। फिर सवाल उठता है कि हम यह पैसे उन्हें किस तरह से दे सकते हैं, इस सदन में यह बात भी कही गई कि इंटरेस्ट रेट्स के बारे में कोई कदम नहीं उठाए गए। यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट के आने से पहले ही एक अच्छा डिसीज़न लिया गया था और वह डिसीज़न था कि अप ट् 50,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट को 11% से 8% करने का निर्णय, जो पुरानी सरकार ने लिया था। यूपीए सरकार के आने के बाद the interest rate has been brought down from 8 per cent to 7 per cent and the limit of Rs.50,000 has been gone up to Rs.3,00,000. यह बात सच है कि इसमें मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, जैसा कि श्री नारायणसामी जी एवं अन्य साथियों ने भी कहा, जहां तक मुझे मालूम है, इस देश के फाइनांस मिनिस्टर at his own level himself call banks and himself take the assessment of each and every bank what is happening about the implementation of this particular scheme. I myself had gone, at least, twice or thrice to NABARD Headquarters and took the review of their entire credit and whatever we have achieved in the last two or three years is definitely remarkable wroth which has been done. Certain decisions have been taken and have been implemented. यह बात सच है और इसमें और अधिक सुधार करने की आवश्यकता है।

आज सबसे ज्यादा गंभीरता की स्थिति कोऑपरेटिव सैक्टर के माध्यम से पैदा हुई है। कोऑपरेटिव सैक्टर का योगदान 27 - 28 प्रतिशत तक नीचे आ गया है। एक जमाने में एग्रीकल्चर क्रेडिट के रूप में 70 से 80 प्रतिशत लोन कोऑपरेटिव सैक्टर के माध्यम से जाता था, लेकिन आज वह कम हुआ है, इसका यहां पर उल्लेख किया भी गया है। यह बात सच है कि आज कई जिलों के डिस्ट्रिक्ट सैन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक ठीक परिस्थितियों में नहीं हैं, उनकी हैल्थ ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए इसी सरकार ने एक वैद्यनाथन कमेटी एपॉइट की थी।

वैद्यनाथन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद entire co-operative system and banking system revise करने के लिए 14 हजार करोड़ रुपए की राशि लगाने की तैयारी की। इसमें 12 हजार करोड़ रुपए भारत सरकार ने देने की तैयारी की। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का ठीक तरह से योगदान चाहिए। यह सब डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक ठीक लाइन पर काम

करने के लिए उनको मजबूत करने की आवश्यकता है। इसको गंभीरता से देखते हुए प्रधान मंत्री जी ने प्रदेश के सभी मुख्य मंत्रियों और सहकारिता मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें मैं और फाइनेंस मिनिस्टर दोनों थे। इस मीटिंग में हर राज्य से अपील की गई कि वैद्यनाथन कमेटी की रिकमंडेशंस के एक्सेप्ट करने के बारे में, और उन्होंने एक्सेप्ट करने के बाद जिन राज्यों ने भारत सरकार के साथ एम0ओ0यू0 साइन किया है, उन सभी बैंकों की परिस्थिति ठीक करने के लिए इसमें कदम उठाने का काम शुरू हुआ है। हम यहां तक रुके हैं ऐसा नहीं है, यह क्रॉप लोन के लिए वैद्यनाथन कमेटी की मदद हो जाएगी। मगर दूसरा जो सैक्टर है टर्म लोन की जो बात है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के साथ-साथ इस देश में जो लैंड डेवलपमेंट बैंक के दूसरे जो बैंक थे, जो किसानों को केपिटल इंवेस्टमेंट के लिए मदद करने वाले थे, उनकी हैल्थ ठीक करने के लिए भी वैद्यनाथन के ऊपर यह जिम्मेदारी दी है। शायद इनकी रिपोर्ट रिसेंटली आई है और इस बारे में भी हम कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। क्रेडिट के क्षेत्र में कोआपरेटिव की हैल्थ सुधारने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देने की तैयारी भारत सरकार के माध्यम से करके आज पूरे देश के कोआपरेटिव इंस्टीट्यूशन मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार इसका लाभ लेंगे और किसानों की ठीक तरह से मदद करने के लिए जल्दी से जल्दी इसमें काम करेंगे। कई माननीय सदस्यों ने एक बात सामने लाई कि यह जो टोटल बोझ है किसानों के ऊपर, इसमें टोटल माफी देने की आवश्यकता है। मुझे मालूम नहीं कि इससे कितना फायदा होगा, यह बात सच है कि इस बारे में कुछ न कुछ सोचने की आवश्यकता है और इसलिए On 10th of August, the Finance Ministry has taken one decision. The Government of India has decided to constitute an Expert Group to look into the problem of agriculture indebtedness in its totality and suggest measures to provide relief to the farmers across the country. The terms of reference and the composition of the Group will be (1) to look into the problems of the agricultural indebtedness in totality, and (2) to suggest measures to provide relief to the farmers across the country. And, that work has been deputed to Prof. R. Radhakrishnan, Director of the Indira Gandhi Institute for Development Research, Mumbai, as the Chairman of the Group along with Dr. P.V. Chenoy, former Secretary (Agriculture), Government of India, Dr. Y.S.P. Thorat, Chairman, NABARD, and Shri Kanta Kumar, former CMD, Syndicate Bank. The Expert Group will submit its report on or before 30th November, 2006.

तो देश के किसानों के ऊपर जो बोझ है, इस बारे में भी सरकार सोच रही है। मगर इस बारे में टोटल स्टडी करके कुछ न कुछ सरकार के सामने एक नक्शा आने की आवश्यकता है। इसलिए डा0 राधाकृष्णन के माध्यम से इनके नेतृत्व में एक ग्रुप कंस्टीट्यूट किया है और मुझे विश्वास है कि अगले 3-4 महीने में इसकी एक टोटल रिपोर्ट सरकार के सामने आएगी और इसमें भी कुछ न कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। इस बारे में हम जरूर देखेंगे। एक और बात यहां सदन के सामने बतलाई गई कि यह जो ग्लोबलाइजेशन होने के बाद इसका असर इस देश के किसानों के ऊपर कुछ न कुछ हुआ है। मुझे एक बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि सॉर्क कंट्रीज के साथ हमारा एग्रीमेंट होने के बाद खास तौर पर प्लांटेशन क्रॉप के विषय में इन राज्यों की परिस्थिति में खराबी हो गई है, पेपर, कॉफी, रबर, कार्डिमम, केरल जैसे राज्यों से

हमारे पास यह शिकायत आ रही हैं कि सॉर्क कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट करने के बाद वहां से मेटीरियल यहां आ रहा है और इस मेटीरियल से यहां के किसानों की परिस्थिति खराब हो रही है।

यह बात सच है कि केरल के जिन जिलों में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं, एक जमाने में वे जिले रिचैस्ट एग्रीकल्चर के बारे में देश में मशहूर थे। इसमें कुछ न कुछ सुधार करने की आवश्यकता है और उसके बारे में पड़ौसी देशों के साथ बातचीत करके, हम इसका कोई रास्ता निकालेंगे। मगर हम यह बात भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि खेती के क्षेत्र में भी हमें एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता है। मैंने सदन के सामने एक बात कही थी कि आज कई क्षेत्रों में, आज दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश हिन्दुस्तान है।

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN (Kerala) : Will you yield for a minute? Sir, with regard to this issue, on the one side, the prices are coming down. I would acknowledge the fact which was mentioned by the Minister that he will look into the matter. On the other side, with regard to the Ministry of Agriculture and the Ministry of Commerce, the problem is that Ministry of Agriculture is not providing any help to the farmers.

SHRI SHARAD PAWAR: I am going to speak on these issues separately.

So, what I am trying to teii is that India is also one of the major producers in the world in many areas. Today, in milk, India is the largest producer in the world. Today, in sugar, India is the second largest producer in the world. In banana, India is the largest producer in the world. In rice, now we have come to the fourth position. In wheat, we have come to fourth position. Forget about this year, there is a specific problem. But there are number of items. In horticulture products, India is the second largest in the world. जब इस देश की जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, हमने उससे ज्यादा उत्पादन करके दिया है और हमें दुनिया का मार्केट देखना होगा। हमने पिछले कई सालों में देखा, In last year also, the total import was Rs. 17,000 crores, and, total exports of the agricultural products from India to outside was Rs. 32,000 crores. हमारा एक्सपोर्ट भी कृषि क्षेत्र में बढ़ रहा है। हम इसका ग्लोबलाइजेशन के नाम पर विरोध करेंगे, तो हम आइसोलेट हो सकते हैं। हमें इस पर ध्यान देना ही होगा। जब हमने यह पालिसी बनाई, हमने देखा है कि कई बार यह सदन, कई इश्युज़ पर बड़ा सेंसेटिव हो जाता है। इस देश का मीडिया भी कई बार बड़ा सेंसेटिव हो जाता है। लास्ट ईयर आपने देखा कि onions के प्राइज़ ऊपर गये, पूरा हंगामा हो गया इस देश में मीडिया के माध्यम से और सदन में भी सदस्य बोलने लगे कि यह क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट बंद करो, एक्सपोर्ट बंद करो। ऐसी परिस्थति पैदा हुई, तो उसको देखकर सरकार ने भी डिसीज़न ले लिया कि No more export of onions. आज, इस साल, इस देश में onions पैदा करने वाले किसानों को आत्महत्या करने की पोजीशन हो गई है। प्रोडक्शन बढ़ गया, मार्केट खत्म हुआ, एक्सपोर्ट करने

के लिए बैन था, बाद में यह बैन उठाया, इंटरनेशनल मार्केट में जो कस्टमर थे, उनका हम पर भरोसा नहीं रहा, उन्होंने कहा कि आप रेगुलर सप्लाई करेंगे, ऐसा आप पर भरोसा नहीं है। इसलिए हम आपके पास से माल लेना नहीं चाहते, इसकी कीमत onions उत्पादकों को इस देश में, इस साल देनी पड़ी।

चाइना की जैसी स्थिति है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। चाइना एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट करता है। राइस की जो रिक्वायरमेंट है, वह रिक्वायरमेंट की पैदावारी इतनी करते हैं, साथ-साथ राइस एक्सपोर्ट भी करते हैं। अगर अपने देश में राइस कम पड़ गया, तो पड़ौसी देशों से राइस इम्पोर्ट भी करते हैं। चाइना वीट का एक्सपोर्ट भी करता है और इम्पोर्ट भी करता है। हमें कभी न कभी इस बारे में शांति से सोचने की आवश्यकता है कि इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट के बारे में हमारा रवैया क्या होना चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए। परिस्थति देखने के बाद, हर साल हमारे डिसिज़न बदलते हैं, इससे हम दुनिया में अच्छा संदेश नहीं भेजते हैं, इससे हमारे ऊपर भरोसा लोगों का नहीं रहेगा। कल cotton के एक्सपोर्ट के बारे में बात हुई, शायद राहुल बजाज साहब और अन्य लोगों ने इस बारे में कुछ कहा। Last year, we have exported 35 lakh bales of cotton and we have imported 6 lakh bales of cotton. हमने cotton किसलिए इम्पोर्ट किया ? देश में cotton का उत्पादन कम नहीं था, मगर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए लॉग स्टेपल cotton की आवश्यकता थी, वह लॉग स्टेपल cotton हमारे यहां उपलब्ध नहीं थी।

जो इस देश में कॉटन पैदा हो रही है, इसमें हमारी लोकल कॉटन और बाहर से लाई जाने वाली कॉटन मिक्स करके हमें टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करने की आवश्यकता थी, इसलिए कुछ इम्पोर्ट करने की भी आवश्यकता हुई। इस प्रकार इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में हमें समझदारी से सोचने की आवश्यकता है। एमएसपी के बारे में कहा गया। किसानों की शिकायत इस बारे में है, यह बात सच है लेकिन एमएसपी देने के लिए कुछ क्राइटेरियाज़ लगाए हैं, एक्सपर्ट ग्रुप अप्वाइंट किया है, किसानों के प्रतिनिधि उसमें हैं, राज्य सरकारों की सलाह इसमें लेते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सलाह इसमें ली जाती है और सब इनफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद इसमें कुछ निर्णय लिया जाता है। एक्सपट्र्स द्वारा लिए गए निर्णय के बाद भारत सरकार इस संबंध में कुछ कदम उठाती है। यह बात सच है जिसको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, जो बात पंजाब के कुछ सदस्यों ने यहां कही कि आज जहां अनाज का उत्पादन ज्यादा होता है, उन राज्यों में बिजली की कमी आती है और बिजली की कमी आ रही है इसलिए डीज़ल पम्प का इस्तेमाल उन लोगों को करना पड़ता है, submersible पम्प का इस्तेमाल भी उनको करना पड़ता है। आज डीज़ल की कीमत बढ़ गयी है, यह बात सच है - दुनिया में बढ़ गयी है। यह सब देखने के बाद अभी कल हम लोगों ने 610 रुपए पैडी की कीमत अनाउंस की। हमारे सब पंजाब के साथी लोगों ने, खास तौर से हमारे सदस्य डा0 गिल और बाकी कई सदस्यों ने पैडी की कीमत के बारे में किसानों की जो भूमिका है, वह सदन के सामने रखने का प्रयास किया। हम लोगों ने इस पर फिर से ध्यान दिया और हमारे सामने यह बात आई कि जो टोटल कीमत हम लोगों ने तय की थी और आज की कॉस्ट में जो बढ़ोत्तरी हुई है, वह देखने के बाद कुछ न कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। हमारे पास 600 रुपए की रिकॅमेंडेशन थी, 610 रुपए करने का हमारा निर्णय था, लेकिन जो बात सदन के कई सदस्यों ने दोनों तरफ से कही, वह सब सुनने के बाद आज पैडी के लिए हम 600 रुपए, जो सीएसीपी की रिपोर्ट थी, रिकॅमेंडेशन थी, इसमें

दस रुपए की जो बात हमने स्वीकृत की थी - इसमें सुधार करने की आवश्यकता है - इस सुझाव को मैं स्वीकार करता हूं और इस साल 600 रुपए की जगह पर 650 रुपए आज पैडी को देने के लिए हम लोगों की तैयारी रहेगी। इससे 40 रुपए की वृद्धि इसमें हो जाएगी। यह जो बाकी कॉस्ट बढ़ रही है, इस पर ध्यान देकर जहां जहां व्यवस्था करने की आवश्यकता है, उसमें हम जरूर व्यवस्था करेंगे, इतना मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। यह सवाल आया कि आत्महत्या के बारे में आप लोग क्या करते हैं? यह बात भी कही गयी कि प्रधानमंत्री विदर्भ में गए। विदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने जाने के बाद कुछ पैकेज अनाउंस किया लेकिन उसके बाद भी वहां पर आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ गयी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो पैकेज चार राज्यों को दिया, वह पैकेज क्या है। जिन जिलों में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई, उसकी स्टडी करने के बाद सबसे पहले हमारे सामने दो बातें आयीं, जिसका मैंने जिक्र किया था। एक, किसानों के ऊपर, जिनके परिवार के सदस्यों ने आत्महत्या की, उन परिवारों के ऊपर कर्जे का बोझ ज्यादा है। इसलिए उस बोझ को कम करने के लिए कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह सामने आयी कि केरल के तीन डिस्ट्रिक्ट छोड़ने के बाद, बाकी तीनों राज्यों के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में पानी की कमी थी, इरीगेशन की कमी थी। इरीगेशन कम था इसलिए टोटल एग्रीकल्चर मानसून के भरोसे पर निर्भर था। इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। तीसरी बात हमारे सामने यह आयी कि जिन किसानों के परिवार के सदस्यों ने आत्महत्या की, उन परिवारों के पास कृषि को छोड़कर सप्लीमेंटरी इनकम का दूसरा कोई आल्टरनेटिव नहीं था, साधन नहीं था। इसलिए जब पैकेज बनाया गया, कुछ न कुछ मदद करने की आवश्यकता है, जब इस पर ध्यान दिया, तब पहला ध्यान इस बात पर दिया गया कि हम क्रेडिट फ्लो को कैसे बढ़ा सकते हैं? दूसरा, जो पुराना लोन उनके ऊपर है, उसकी रीशेडयूलमेंट कैसे कर सकते हैं। तीसरा, रीशेड्यूलमेंट करने के बाद इंटरस्ट का बोझ फिर से बढ़ता है, उस इंटरस्ट को कैसे माफ कर सकते हैं। जो कल यहां बतलाया गया, शायद वर्मा जी ने कहा कि आप लोगों ने उनको क्रेडिट देने का प्रबंध नहीं किया।

मगर जो डीफॉल्टर हैं, उनको कैसे पैसा मिलेगा? जिन 31 जिलों में यह पैकेज announce किया, वहां हर किसान की total liability को reschedule किया, सात साल के लिए। दो साल के लिए उनको moratorium दे दिया और बैंकों को instructions दिए कि उनकी पुरानी रिकवरी नहीं आई, यह बात सच है, लेकिन यह सच होने के बावजूद उनकी credit line आपको ओपन करनी चाहिए और उनको नया पैसा देने का प्रबंध कर देना चाहिए, इस तरह के directions through the Reserve Bank of India and through NABARD, सभी बैंकों को दिए हैं और इसका अमल आज विदर्भ में होना शुरू हुआ है। साथ-साथ उनका जो interest का पुराना burden था, वह पचास प्रतिशत राज्य सरकार ने और पचास प्रतिशत भारत सरकार ने देकर पूरा किया है। जहां तक विदर्भ की बात प्रधान मंत्री ने announce की है, वह announcement करने के बाद, जो 800 करोड़ के आसपास interest की liability थी, वह बढ़ने की व्यवस्था सरकार ने की है और यह कहा गया है कि किसानों तक कुछ पहुंचा नहीं, तो ये पैसे किसानों तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि interest का burden किसानों के ऊपर जो था, वह बैंक का burden था। वे पैसे बैंक में उनके नाम पर थे, इसलिए उनका बोझ कम हो गया और इनसे छुटकारा पाने के लिए जो कदम उठाने की आवश्यकता थी, वह काम इसमें हुआ है।

दूसरा काम क्या किया था? Assured irrigation, micro irrigation, watershed development, water harvesting scheme, check dam - इस काम के लिए सबसे ज्यादा पैसे दिए। विदर्भ के पैकेज में 2200 या 2300 करोड़ के आसपास का amount इस काम के लिए दिया गया है। इरिगेशन के प्रोजेक्ट का डिसीजन क्या है, इरिगेशन का डिसीजन है कि विदर्भ के 6 जिले हैं, इन 6 जिलों में जितने minor, medium and major projects हैं और जहां Environment & Forests Department का clearance है, ये सभी के सभी प्रोजेक्ट तीन साल में पूरे करने हैं और तीन साल में पूरा करने के लिए जो राशि लगेगी, वह पूरी राशि भारत सरकार AIDP के माध्यम से देगी और वह इसका प्रबंध करने के लिए तैयार है।

कई सदस्यों ने कहा कि आप लोगों ने काम शुरू नहीं किया। पिछले हफ्ते तक विदर्भ में सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की थी। इतने बड़े पैमाने पर बारिश वहां हो गई कि हर नदी का पानी था और सदन को मालूम है, सदन के सभी माननीय सदस्यों को मालूम है कि जब मानसून आता है, तब हम इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स के काम कभी शुरू नहीं कर सकते और इसलिए, जुलाई महीने के फर्स्ट वीक में प्रधान मंत्री वहां गए थे। उसी दिन वर्धा में जाने के बाद, वहां डीटेल्ड डिसकशन करने के बाद, नागपुर में उन्होंने announcement किया। राज्य सरकार की मीटिंग बुलाई और राज्य सरकार को क्या-क्या दिया है, इस बारे में टोटल information दे दी। इरिगेशन डिपार्टमेंट के सभी प्रोजेक्ट्स approved हैं, इसका clearance सरकार ने भेजा है और राज्य सरकार को instructions दी हैं कि इस तरह से पैसे का प्रबंध हमने किया है। राज्य सरकार ने यह कहा कि मानसून का season खत्म होने के बाद हम ध्यान देंगे, तो वहां काम शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रधान मंत्री ने announcement की और दूसरे दिन ही परिस्थिति में बदलाव आएगा, ऐसी समझ रखना मुझे ठीक नहीं लगता। ...**(व्यवधान)**...

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI (Maharashtra) : In one day alone, yesterday, eleven farmers committed suicide.

SHRI SHARAD PAWAR: I do not know, but I heard your speech yesterday. You have made one request that whatever money is being provided to the families, where suicide took place, it should be totally stopped. Mr. Sharad Joshi made a statement yesterday that it became an incentive for suicide. That was his statement.

श्री दत्ता मेघे : वह उनकी बात है, लेकिन लोगों को जो पैसा मिला, उससे उनको फायदा हुआ और सभी लोगों ने इसका स्वागत किया। यह उनकी व्यक्तिगत राय है। ...**(व्यवधान)**...यह बराबर भी है, जिन लोगों को पैसा मिला, ये भी ...**(व्यवधान)**...

श्री शरद अनंतराव जोशी : विदर्भ के किसानों को मैं ज्यादा अच्छा जानता हूं।

SHRI MANOHAR JOSHI (Maharashtra) : On the same issue, I want to ask the hon. Agriculture Minister only one question about the amount that is provided in the Budget on different items. I am talking about the Prime Minister's package. Apart from the amounts which are provided every year, what is the additional amount provided?

SHRI SHARAD PAWAR: This amount is entirely additional amount. Whatever money has been provided for irrigation is additional amount which shall be provided from AIBP. Then, secondly, about interest, that will be provided absolutely additionally. It is an additional amount. Then, replacement of seed, अच्छी तरह से seed का इस्तेमाल करने के बाद किसानों को यह कार्यक्रम लेना चाहिए। इसमें 50 per cent subsidy है, This is entirely an additional amount. Then, subsidiary income को improve करने के लिए livestock cattle के लिए हर district में 1,000 cross breed cows हर साल purchase करके उन परिवारों को distribute करने का कार्यक्रम 3 साल के लिए हमने लिया है, जिसमें 50 per cent amount is subsidy which will be provided from the Government of India and the 50 per cent will be provided through financial institutions. That means, hundred per cent. Of course, fifty per cent is a loan, but fifty per cent is an outright grant that will be provided from the Government of India and like that, the entire programme has been prepared. The programme is not only prepared for Maharashtra and Vidarbha, but similar programme has been prepared for Andhra, Karnataka and Kerala, इन तीनों राज्यों के लिए है। इसमें एक बात है ...(**व्यवधान**)... Let me complete. ...(*Interruptions*)... Let me complete.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): I think, let the hon. Minister complete now. Please.

श्री शरद पवार : उपसभाध्यक्ष महोदय, इन तीनों राज्यों का proposal हमारे पास आया है और इसकी study करने के बाद यह proposal गवर्नमेंट के सामने final decision के लिए आया है और मैं इस सदन के माध्यम से तीनों राज्यों के लोगों को और वहां की गवर्नमेंट को यह बताना चाहता हूं कि आने वाले 15 दिनों में केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्यों के proposals को हम clear करेंगे और इस बारे में जो भी कदम उठाने की आवश्यकता है, वह कदम हम उठाएंगे। इसमें एक बात है कि यह proposal तैयार करने के बाद राज्य सरकार के नए सुझाव आ गए। मेघे साहब ने कहा कि 6 districts के लिए आपने कुछ नहीं किया, यह बात सच है, विदर्भ के अतिरिक्त और जिलों की समस्या इतनी गंभीर है - Bhandara, Yavatmal, Gadchiroli, Chandrapur, इन जिलों की भी समस्या है, लेकिन हमने इनमें कोई न कोई criterion लगाया है और उस criterion में highest percentage of suicides का criterion लगाया है। इस बारे में राज्य सरकार ने proposal दिया था, महाराष्ट्र सरकार ने यह proposal दिया था, जिस पर भारत सरकार ने decision ले लिया है। ऐसी ही समस्या आ गई। आंध्र प्रदेश की सरकार ने 16 districts का proposal दिया, हमने उसे totally स्वीकार किया, केरल की सरकार ने 3 districts का proposal दिया, हमने totally स्वीकार किया। अभी केरल में सरकार बदल गई ...(**व्यवधान**)...

PROF. P.J. KURIEN (Kerala) : Sir, two more were given. Kerala Government has given names of two more districts, Idukki and Alleppey, in addition -- a total of five districts, not three.

SHRI SHARAD PAWAR: That is not correct. I am sorry. Kerala had sent a written proposal for three districts. After the elections, when a new Government came, they have included another two districts, that is, Idukki and Alapphuza. This is a new proposal. What we have decided is that कि जो पुराना proposal हमारे सामने है, हम उसे पहले पूरा करना चाहते हैं और यह जो बात यहां पर कही गई है, खास तौर से पंजाब के सदस्यों ने कही है कि किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं केवल इन चार राज्यों तक सीमित नहीं हैं, देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इनके पीछे कर्ज़ का बोझ एक महत्वपूर्ण कारण है, इन सब चीजों को देखने के लिए डा. राधाकृष्णन कमेटी appoint की गई है, जिसके माध्यम से हिंदुस्तान के सभी राज्यों के किसानों के कर्ज़ की जो समस्या है, उसका हल निकलेगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए यह कदम उठाया गया है और मुझे विश्वास है कि 4 राज्यों का उदाहरण हमारे सामने आने के बाद, इसका result देखने के बाद, बाकी राज्यों को भी इस क्षेत्र में क्या मदद कर सकते हैं, इस बारे में सरकार बड़ी गंभीरता से ध्यान दे रही है, यह मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं। कुछ और बातें यहां पर कही गईं, खास तौर पर वर्मा जी ने National Exchanges के बारे में कहा कि There are 21 regional exchanges and they are not working.

> "Both the Exchanges have terminal all over the country and trading is on line exactly as like in National Stock Exchanges. Then, the brokers have clients in every part of the country and they trade though these Exchanges. There are over 2,100 members across the country and they are spread all over the country, in small towns, north, south, east, west. Even though the Exchanges are located in Mumbai, local traders from all over the country can participate. Every day, thousands of clients from all over India are participating."

इसलिए एक्सचेंज का हेडक्वार्टर वहाँ है, मगर यह काम पूरे देश में आज भी चालू है।

श्री विक्रम वर्मा : माननीय मंत्री जी, जिस तरह से शेयर मार्केट के लिए सेबी जैसी कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, इसके लिए भी कोई रेग्युलेटरी अथॉरिटी तो हो। ऐसा नहीं होने पर जब-तब वे भाव बढ़ा देते हैं और जब किसान के पास स्टॉक है, चाहे जब गिरा देते हैं। इसके लिए भी एक रेग्युलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। अन्यथा इससे एग्रीकल्चर पर ही सट्टा चालू हो जाएगा। शेयर मार्केट जैसा एक नया सट्टा बाजार चल रहा है।

श्री शरद पवार : इसमें रेग्युलेटरी अथॉरिटी अप्वायंट करने के लिए और कोई व्यवस्था करने के लिए कानून में प्रावधान करके सदन के सामने एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। बिल आज सदन के सामने है। उसके क्लियर होने के बाद आप जैसा कह रहे हैं, इससे कोई रास्ता निकलेगा। इसमें किसी मशीनरी की आवश्यकता है, इस मशीनरी के बारे में हमने ध्यान दिया है और कदम उठाए गए हैं।

सर, एक सवाल यहाँ यह उठाया गया कि हम लोगों ने अमेरिका के साथ कुछ किया है, इसमें शायद मोनसेंटो और अन्य लोगों की मदद करने के लिए ऐसा किया है। यह बात सच है कि जब प्रधान मंत्री अमेरिका गए थे, तब अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ detailed discussion करके Indo-US Agriculture Knowledge Initiative के बारे में एक एग्रीमेंट करने की बात हुई और एक एग्रीमेंट किया गया है। यह Knowledge Initiative किस क्षेत्र में है, that is Agriculture Education, Research Services and Commercial Linkages. Education, Learning Researches, Curriculum Development and Training. दूसरा सब्जेक्ट है, Food Processing, Use of the Bio-products and Bio-fuel. तीसरा सब्जेक्ट है, Bio-technology और चौथा सब्जेक्ट है, Water Management. इन चार क्षेत्रों में अमेरिका में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। अपने देश में भी इसका लाभ उठाने की आवश्यकता है। इसी काम के लिए इसमें ध्यान दिया गया है। इसमें मोनसेंटो की मदद करने के लिए कोई कदम उठाया गया है, यह बात सच नहीं है। यह प्रोग्राम स्पेसिफिक है और इसका काम शुरू हो रहा है।

सर, यहाँ एक बात और कही गई कि जो नया प्लान, 11th प्लान बन रहा है, इसमें एग्रीकल्चर को totally neglect किया गया है, इस तरह की परिस्थिति आज सदन के सामने रखी गई है। इसमें सच्चाई नहीं है। एक बात सच है कि इसमें एग्रीकल्चर पर हम ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। जब हम एग्रीकल्चर पर ध्यान देना चाहते हैं, तो इसमें हम स्टेट्स के views भी लेना चाहते हैं। इसलिए अब जो 11th प्लान बनने वाला है, इसमें एग्रीकल्चर को ज्यादा importance देने के लिए हमने 6 सेक्टर्स identify किए हैं। इन 6 सेक्टर्स में, 6 सब्जेक्ट्स में, कुछ मुख्य मंत्रियों को involve करके उनकी मदद से, उनकी सलाह लेकर आगे के प्लान में उस प्लान का नक्शा किस तरह होना चाहिए, इसमें कुछ कदम उठाए गए हैं। पहला सब्जेक्ट है, Marketing Reform and Contract Farming under the chairmanship of Chief Minister of Punjab. पंजाब के चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में एक ग्रुप constitute किया गया है, उसका काम पूरा हो रहा है। दूसरा ग्रुप constitute किया गया है, under the chairmanship of Chief Minister of Maharashtra, सब्जेक्ट है Irrigation, Minor Irrigation. यह जिम्मेदारी उनके ऊपर दी गई है। तीसरा ग्रुप constitute किया गया है, वह Chief Minister of Gujarat के नेतृत्व में है। इन्हें जिम्मेदारी दी गई है, Dry Land, Rainfed Farming System, including regeneration of the Degraded Wasteland and Watershed Development Programme. For this prgoramme, we have given this Committee's responsibility to the Gujarat Chief Minister. चौथी जिम्मेदारी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के ऊपर दी गई है। इसमें Crop-specific Productivity Analysis and Agro-climatic Zone-- This particular subject has been given to the Orissa Chief Minister, and under the chairmanship of Member, Agriculture, Planning Commission. इनकी अध्यक्षता में Credit and Risk Management की जिम्मेदारी दी गई है। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में Animal Husbandry, Dairy, Poultry and Fishery की जिम्मेदारी दी गई है।

इन सभी subjects के बारे में ये ग्रुप अपनी रिपोर्ट तयार करेंगे और इस रिपोर्ट के सजेशंस प्लान में incorporate करने पर ध्यान दिया जाएगा, यह मैं सदन को विश्वास दिलाना

चाहता हूं। तो overall जो परिस्थिति है, परिस्थिति गंभीर है, मगर भारत सरकार ने इस का cognizance लिया है। मुझे एक बात कहने में खुशी होती है कि आज एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी दुरुस्ती की आवश्यकता है, चाहे क्रेडिट के क्षेत्र में हो, इरिगेशन के क्षेत्र में हो, सप्लीमेंटरी इनकम के बारे में हो, सीड के बारे में, हॉर्टीकल्चर के बारे में हो, मार्केटिंग के बारे में हो, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के बारे में हो - इन दो सालों में टोटल बजटरी प्रोवीजंस और नई-नई स्कीम्स जो निकाली हैं, वे कई सालों में नहीं निकाली थीं। डा0 मनमोहन सिंह के नेतृत्व में इस में जो परिवर्तन की आवश्यकता है, उस का cognizance बड़ी गंभीरता से इस भारत सरकार ने लिया है और आज जो परिस्थिति आत्म-हत्या की है, इस में जल्दी-से-जल्दी कैसे सुधार हो, इस पर हमारा ध्यान रहेगा। मैं इतना ही सदन के सामने कहना चाहता हूं।

महोदय, एक personal बात यहां कही गयी। मैं इस का जिक्र नहीं करना चाहता था, मगर जनेश्वर मिश्र जी जो यहां नहीं हैं, उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर को समय नहीं मिलता। वह क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यह बात सच है कि मैं देश की कई संस्थाओं का अध्यक्ष हूं। मैं क्रिकेट का अध्यक्ष हूं, महाराष्ट्र wrestling का अध्यक्ष हूं, महाराष्ट्र ओलंपिक का अध्यक्ष हूं, मैं कई खेलों की जिम्मेदारी लेता हूं, कई क्षेत्रों में काम करता हूं, मगर एक बात सच है कि मेरी जो जिम्मेदारी है, उस से मैं compromise नहीं करता हूं।

I should not take liberty. It is not proper for me to tell you this thing. I am one of the Ministers, like my other colleagues, who clear every proposal and every file within 24 hours. I am one of the persons who is attending the office from 9.45 A.M. up to 6.00 P.M. every day. The time that I am spending on these types of activities is not more than two hours a week. I think it is sufficient because I believe in decentralisation. I distribute work and I generally give them guidelines. I would like to assure the people of this country and, especially, the farming community of this country that at the cost of Indian farmers and the agriculture sector I would never do anything. My topmost priority is agriculture and agriculturists and to see that the situation is altogether changed in these five years. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Thank you, Mr. Minister. ...(*Interruptions*)... Just one minute. ...(*Interruptions*)...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Yesterday, I had raised the problem of cash crop farmers. It is not a simple thing. What I had raised was regarding the problem of cash crop farmers who are not getting the benefit because of the existing norms prevailing in this country. The hon. Minister has to tell this House how he is going to help them. He has to relax some of the norms. Some assurance has to be given to the farmers. That is the thing. ...(*Interruptions*)... In a district like Idukki the problem is very serious. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): You have made your point. ...(*Interruptions*)...You take your seat. ...(*Interruptions*)... You have made your point. ...(*Interruptions*)...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Let him give an assurance to this House. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): You have made your point. ...(*Interruptions*)...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Let him give an assurance. ...(*Interruptions*)... Why should we come and raise the issue in this House? ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Will you listen to me? I personally feel that the hon. Minister has at length discussed the whole thing. If there are certain clarifications, I may permit. ...(*Interruptions*)...

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: This is not the answer. ...(*Interruptions*)... If he is not answering, I have to go to the people... ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): I may permit two or three clarifications, if the hon. Minister is ready.

SHRI SHARAD PAWAR: It is true that there is a different problem in Kerala. They are essentially taking plantation crops and we have prepared a package. The reason for the delay is that we have realised that we have to take a little different approach, especially, in respect of Kerala because of their plantation crops. We are thinking of that type of corrective actions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): I can permit if there are no speeches, if there are very short questions and if the hon. Minister is ready to answer. Shri Vijay Darda.

SHRI ANANTRAO SHARAD JOSHI: Sir, on the merits of his reply, the farmers will not vote them in the coming months.

3.00 P.M.

श्री विजय जे0 दर्डा (महाराष्ट्र) : सर, कल मैंने सम्माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न पूछा था, जिसका उन्होंने अपने भाषण में उल्लेख नहीं किया। इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन चाहूँगा कि आत्महत्या क्यों हुई, इन्होंने क्या प्रयास किए, क्या इसका कारण कृषि नीति है या आर्थिक नीति, यह मेरा प्रश्न था। दूसरा मैंने यह कहा था कि क्रॉप पैटर्न जो है, जैसे विदर्भ में कपास एक खास क्रॉप पैटर्न है, तो अगर लॉंग स्टेप्ल का कपास पैदा होता है, तो क्या उसकी नीति नहीं बनाई जा सकती, जिसके माध्यम से वहाँ बाहर के भी किसान आकर उसको बनाएँ।

तीसरी बात मैंने बैंक्स के रवैये के बारे में कही थी। मैंने बैंक से सम्बन्धित एक स्पेसिफिक केस दिया था कि किस प्रकार से वह बैंक मैनेजर पूछता है कि आप गाय का दूध निकालना जानते हैं, इसका सर्टिफिकेट लाइए। वह आदमी 40 लाख रुपए की अपनी जमीन गिरवी रखने के लिए तैयार है और उसके एवज़ में वह डेढ़ लाख रुपए माँग रहा है, लेकिन मैनेजर उसे देने से मना करता है तथा उसे अंग्रेजी में लिखकर देता है। आपने उसके बारे में भी नहीं कहा।

मैंने एक बात और कही थी कि जो पैकेज दिया गया है, उसमें अगर हम प्रति किसान विचार करें, तो वह 725 रुपए आता है। तो मैं चाहूँगा कि आदरणीय मंत्री महोदय इसके बारे में कुछ कहें।

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी): आप सब प्वायंट्स पहले ले लेंगे या एक-एक करके जवाब देंगे? ...**(व्यवधान)**... पहले सब ले लेंगे ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय जे0 दर्डा : सर, एक-एक का रहेगा, तो अच्छा रहेगा ...**(व्यवधान)**...

SHRI MANOHAR JOSHI : Sir, I am only on one point. He has given an exhaustive answer to the debate wherein he has listed a number of remedies as well. But these are all long-term measures, and I don't think the measures, that the Minister has suggested, can stop suicides of farmers. As my friend, hon. Member, Shri Sharad Joshi, just now said, yesterday itself, nine farmers have committed suicide. Therefore, a number of Members from various political parties have suggested that not only interest but it is also necessary that whatever loans the farmers have taken, they have to be waived, for the time being, at least during these difficult times of the farmers. Will the hon. Minister do something to stop the suicides of farmers by waiving off the loans that they have taken?

प्रो0 राम देव भंडारी (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से सभी विन्दुओं पर प्रकाश डाला है। 40 percent assured irrigated land है। 60 परसेंट वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। महोदय, उसके साथ नैचुरल कैलामिटी है। सरकार ने फसल बीमा योजना चलाई हुई है। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूँगा कि इस समय फसल बीमा योजना की क्या स्थिति है। अगर किसानों की फसल का बीमा हो जाता है, उसकी फसल नुकसान के बाद उसे पैसा जाता मिल जाता है। सरकार की क्या पॉलिसी है, इस सम्बन्ध में?

इस समय कैसा चल रहा है, आगे साझा पॉलिसी थी क्या? मैं जानना चाहता हूँ? धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Shri Ravula Chandra Sekar Reddy. Please be very brief. We have already had a discussion, and we cannot restart it.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Yesterday, I raised a point regarding fixation of prices. As production varies from zone to zone, it will be costing less in Southern parts, and it will be costing more in Northern parts. I wanted zonal representation in the Price Fixation Committee. That is one suggestion. The second one is that in Andhra Pradesh alone, 3,247 farmers have committed suicide since May, 2004, till yesterday ...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: You give the earlier figure as well.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: You must be having that figure...(*Interruptions*)... Sir, that is how a controversy arises. Now they are in Government ...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: You started from May, 2004. That is why I am asking...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Mr. Narayanasamy, are you going to reply?

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: They made a hue and cry during 2004 elections that farmers were committing suicides. Now, you are in power; you are in the Government, both at the Centre and in the State. It is your responsibility to see that ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Now, Mr. Bhandary. ...(*Interruptions*)... Please be brief.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, I have not completed. Sir, 3247 farmers have committed suicide in Andhra Pradesh. The hon. Prime Minister has also visited the State of Andhra Pradesh. But, so far, nothing has happened. Sir, the present Government of Andhra Pradesh has sent a request to the Central Government for a special package of Rs.51,856 crores, in which about Rs.1,500 crores is as interest waiver. At least, to the extent of interest waiver, it is an immediate and urgent need. What is the response of the hon. Minister, in this regard?

श्री दत्ता मेघे : सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक क्वैश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसा मनोहर जोशी जी ने कहा, क्या पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ हो सकता है? जब वह चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कोई 127 करोड़ का कर्जा माफ किया था। मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहूंगा कि आप कोई ऐसी वाल्युंटरी स्कीम हमारे देश में लाएं और उससे जो पैसा आए, क्योंकि हमारे देश में अभी भी बहुत ब्लैक मनी है, वाल्युंटरी स्कीम लाओ और व्हाइट बनाओ, इससे 30 परसेंट जो पैसा आएगा, उस पैसे से आप किसानों का पूरा कर्जा माफ कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसी स्कीम फाइनेन्स मिनिस्टर साहब लाएंगे?

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अध्ययन के बारे में बताया था कि 40 फीसदी किसान ऐसे हैं, जो चाहते हैं कि किसानी न करें। उसमें यह भी है कि लगभग 49 फीसदी किसान ऐसे हैं, जो कर्जे के भार से बड़े दबे हुए हैं। एक और सर्वेक्षण के अंदर जो दिया गया है, उसकी तरफ भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो भूमिहीन किसान हैं, जिनकी संख्या पहले 35.4 फीसदी थी, वह बढ़ कर 40 या 41 फीसदी हो गई है और उसी तरीके से जो सीमांत कृषक हैं, उनकी भी संख्या बढ़ती जा रही है। मेरा ध्यान आकर्षित करने का तात्पर्य यह है कि इनमें से, जैसा आपने कहा कि एक लाख से ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं, इसमें किसानों की ज्यादा हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भूमिहीन किसानों में और लघु सीमांत किसानों में बहुत से कृषक-मजदूर के नाते भी काम करते हैं, खेतिहर मजदूर के नाते भी काम करते हैं। इसके कारण या भूख के कारण इनकी आत्महत्याएं करने की कई घटनाएं भी सामने आई हैं। हम लोगों के सामने भी आती रही हैं, उसका क्या आंकड़ा है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं जानना चाहता हूँ कि इनके लिए क्या कोई विशेष योजना है, ताकि ये अपनी आजीविका ढंग से चला सकें। क्या इनके कोई इंटीग्रेटेड प्लान, जो समग्र योजना हो, इस दृष्टि से कोई तैयार की गई है?

PROF. P.J. KURIEN: Sir, I said that the Government of Kerala has proposed five districts for special package.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): We have restarted the debate. ...(*Interruptions*)... We have already restarted the whole thing. ..(*Interruptions*)... Please put pointed questions.

PROF. P.J. KURIEN: Sir, the hon. Minister has already agreed that there are five districts, but proposed in two instalments -- first, second and the third. He has also said about the three districts which the Government has already cleared, and the details are coming. But, with regard to the other two districts, namely, Idukki and Alleppey, he has said that it would be considered. But, I would like to know from the hon. Minister by which time the package will be announced.

श्री राशिद अल्वी (आन्ध्र प्रदेश) : वाइस चेयरमैन सर, मंत्री जी ने ने बहुत डिटेल में अपना जवाब दिया, जिनसे बहुत सारी बातें समझने का मौका मिला। मैं उनको मुबारकवाद देता हूँ, लेकिन उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जैसा मंत्री जी ने कहा कि 40 परसेंट फार्मर्स किसानी छोड़ देना चाहते हैं। जो छोटे किसान हैं, उनके पास एक एकड़, दो एकड़ जमीन है,

बहुत सारी स्टेट्स के अंदर वहां की सरकारें उस लैंड को एक्वायर कर लेती हैं और उन्हें पैसा दिया जाता है, जो वह खत्म कर देते हैं और बेरोजगार हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर यह भी हो रहा है, एक मूवमेंट भी चल रहा है कि सरकार लैंड एक्वायर करके बड़े इंडस्ट्रिलिस्ट्स को देती है। ...**(व्यवधान)**...

श्री वीरेन्द्र भाटिया (उत्तर प्रदेश): सर। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी): वह मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री वीरेन्द्र भाटिया : सर, उत्तर प्रदेश का नाम बीच में कहां से आ गया? ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी): वह तो मंत्री जी बता देंगे। ...**(व्यवधान)**... आपका पाइंट समझ गया, वह आ गया है। मंत्री जी जवाब दे देंगे। ।...**(व्यवधान)**...

श्री वीरेन्द्र भाटिया : मंत्री जी क्या जवाब देंगे? यह तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। एक तरह से सीधे-सीधे आक्षेप लगा रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री राशिद अल्वी : सर, दादरी के 100 लोगों को गाजियाबाद की जेल में बंद कर दिया। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी) : बस, आपकी बात हो गई, मंत्री जी जवाब दे देंगे। वर्मा जी, आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री वीरेन्द्र भाटिया : सर, ये आक्षेप लगा रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री राशिद अल्वी : सर, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूं। इस तरह डिस्टर्ब तो नहीं किया जाता। ...**(व्यवधान)**....

श्री वीरेन्द्र भाटिया : डिस्टर्ब आप कर रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री राशिद अल्वी : मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि क्या सैंट्रल गवर्नमेंट कोई कदम उठा रही है? ...**(व्यवधान)**....

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी) : वर्मा जी, आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**... राशिद जी, आपका प्वाइंट आ गया, मंत्री जी जवाब देंगे। ...**(व्यवधान)**... मंत्री जी ने आपका प्वाइंट नोट कर लिया है, वे जवाब देंगे। ...**(व्यवधान)**... वर्मा जी, आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**....

श्री विक्रम वर्मा : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय मनोहर जोशी जी ने प्रश्न पूछा, आज की स्थिति में जो देश के किसानों की हालत है और जो एकदम आत्महत्या के कगार पर हैं, उनके लिए वह एक मात्र ...**(व्यवधान)**... इसका जवाब तो माननीय मंत्री जी देंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री वीरेन्द्र भाटिया : *

श्री राशिद अल्वी : *

श्री वीरेन्द्र भाटिया : *

श्री राशिद अल्वी : *

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी): अल्वी जी, ...**(व्यवधान)**... Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*... Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*... अब हो गया न, आप कृपया बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए, प्लीज़। ...**(व्यवधान)**... वर्मा जी, आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**... देखिए, यह गलत बात है।

श्री विक्रम वर्मा : उपसभाध्यक्ष जी, कल मैंने एक प्रश्न उठाया था, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन का जो बिल आना है, जो एक्सपर्ट कमिटी बनी थी, वह exclusively for agricultural products के लिए था, लेकिन उस बिल में इस प्रकार की छेड़खानी की जा रही है, जिसके बारे में मैंने कल उल्लेख किया था, माननीय मंत्री जी कृपया उस बारे में जरूर बताएं।

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़) : मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कल मैंने उनका एक समाचार पत्र में सचित्र बहुत अच्छा विचार पढ़ा।

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी) : आपका कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है।

श्री श्रीगोपाल व्यास : उन्होंने यह कहा है कि जिन लोगों ने गोवंश से अतिरिक्त आय प्राप्त की है, ऐसे परिवारों में आत्महत्याएं कम हुई हैं या नहीं हुई हैं, ऐसा समाचार मैंने उनके वक्तव्य के माध्यम से पढ़ा है। दूसरी ओर, मुझे सेवाग्राम वर्धा से जो मिला है, उसकी दो लाइनें मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, आपका जो विचार हो आप बता दें।

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी) : नहीं, अभी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए।

श्री श्रीगोपाल व्यास : हजारों कत्लखाने देश में खोले जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि सरकार ने उनको सब्सिडी दी है, इस विषय पर चर्चा नहीं हुई है। पशुधन के बारे में आपने बहुत अच्छा विचार रखा था, उसका स्पष्टीकरण कर दीजिए, इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Sir, the Finance Minister is also sitting here along with the Agricultural Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): You have to ask the Agriculture Minister, not the Finance Minister.

---

* Not recorded.

SHRI JANARDHANA POOJARY: I just would like to bring to your notice a heart-breaking incident; of course, there are so many incidents. In Karnataka, seven children of one farmer have committed suicide in a day. There are so many incidents like that. One family of an agriculturist, a small farmer, after taking loan from a bank, went in for four bore wells but he could not get water. Because of that the family committed suicide. I just would like to bring to the notice of the hon. Finance Minister and the Agricultural Minister that when they are in debt, they would not be in a position to pay back for years; if you are going to reschedule the loan for 7 or 10 years, during their life time, they will not be in a position to pay it back. After all, why are you keeping them under debt for years together when banks are not going to get that money? Why cannot you write it off? That is why, I agree with Joshiji that you write it off. You have written off the debt of big industrial houses. You have written off thousands of crores of rupees.

You did not want to give them. ...*(Interruptions)*... Now why can't you change the law, when we are dead sure that you are not going to get back the money? ...*(Interruptions)*...

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश): सर, मैं एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। संयोग से आज यहां पर वित्त मंत्री जी भी बैठे हुए हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी): नहीं, अब बहुत हो गया है ...**(व्यवधान)**...।

श्री गांधी आज़ाद: नहीं सर, मैं एक बहुत ही सीधा सवाल पूछ रहा हूं ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी): सभी के सवाल सीधे ही होते हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री गांधी आज़ाद: संयोग से यहां पर कृषि मंत्री जी भी बैठे हैं और वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं। मैं सदन के माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि बैंको का जो एनपीए है, वह कृषि क्षेत्र में कितना है और औद्योगिक क्षेत्र में कितना है? अगर एनपीए है, तो किसानों का माफ क्यों नहीं किया जा सकता है ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश त्रिवेदी): यह तो क्वेश्चन आवर का सवाल हो गया है, यह क्वेश्चन आवर का सवाल हो गया है।

श्री गांधी आज़ाद: अगर एनपीए है, तो किसानों का माफ क्यों नहीं किया जा सकता है...**(व्यवधान)**...

SHRI SHARAD PAWAR: Sir, regarding the Warehousing Bill, I would submit that it is before the Parliament. If he wants to make any

suggestions, he will definitely get an opportunity for that and we will take corrective action.

Many Members have raised the issue of indebtedness. I have replied that a Committee has recently been appointed under the chairmanship of Mr. Radhakrishnan, which is going to look into this particular subject. This subject has been raised by many Members including Mr. Meghe, Mr. Joshi, and also Mr. Poojary. So, I have read the Terms of Reference and in that on the same issue work has been handed over to them. After getting their report, the Government will take appropriate action.

Now, Prof. Kurien raised the question of package for six districts. I have said that we had proposal from the previous Government for three districts. We are going to take the final view on three districts and then we will definitely consider sympathetically the rest of the few districts.

जहां तक भंडारी जी ने फसल बीमा की बात उठाई है, आज देश में फसल बीमा की योजना चालू है, इसमें कुछ सुधार किए जाने का प्रस्ताव भी है और उस सुधार किए जाने के बारे में मैंने सदन में इससे पहले भी कहा था। सुधार खास तौर पर यह किया जाना है कि आज जो ब्लॉक यूनिट है, वह ब्लॉक यूनिट छोड़ कर पंचायत यूनिट करने के बारे में विचार चल रहा है, जो अब फाइनल स्टेज में है। सरकार बहुत जल्द ही इस बारे में कोई निर्णय लेगी।

श्री दर्डा ने एक इंडिवीजुअल केस के बारे में बताया है, इस बारे में मैं अभी जवाब नहीं दे सकूंगा क्योंकि उस फार्मर ने कौन से बैंक में एप्लीकेशन दी, क्या सवाल पूछा गया, वहां के बैंक मैनेजर ने उनको क्या जवाब दिया, यह सब इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय जे. दर्डा: क्या सरकार उस पर कोई इंक्वायरी करवाएगी?

SHRI SHARAD PAWAR: That is not my subject also.

Mr. Reddy has raised the issue of CSCP. Generally in the CSCP, at the time of discussion on MSP, they take into consideration the following points:

(1) Cost of production (2) changes in input prices (3) input and output price parity (4) trends in market prices (5) demand and supply situation (6) inter-crop prices parity (7) effect of the industrial cost structure (8) effect of price waiver (9) effect of the cost of living (10) international market price situation and (11) parity between the prices paid and price received by the farmers in terms of trade.

Mr. Reddy has given a suggestion that we should try to accommodate the State representatives. I will consider that suggestion because that will be useful. Thank you very much.

GOVERNMENT BILLS

The Constitution (Eighty-Seventh Amendment) Bill, 1999

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH TRIVEDI): Now we shall take up the Constitution (Eighty-seventh Amendment) Bill, 1999.

THE MINISTER OF PANCHAYATI RAJ AND MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI MANI SHANKAR AIYAR): Sir, I move for leave to withdraw the Constitution (Eighty-seventh Amendment) Bill, 1999.

The question was proposed.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, this Bill pertains to Andhra Pradesh, the proposal was received from Andhra Pradesh. The main purpose of bringing this Bill at that time was -- Jairamji is aware of the problem -- this. There is a three-tier system and five functionaries in Panchayati Raj in Andhra Pradesh. It was agreed in principle; the Bill was brought to the House. But due to some other reasons it was delayed. Now you are withdrawing it. What exactly is the reason?

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, I am not sure why you should look at Shri Jairam Ramesh? ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: It is under consideration that it will be passed.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, I represent the country here. May I respond to it?

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Unfortunately, the Bill originated from Andhra Pradesh. I am afraid, you represent country. But, unfortunately, the Bill originated from Andhra Pradesh. He is aware of the problem.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR: Sir, this Bill was brought in the previous Lok Sabha, when there was another Government sitting on this side, and we were sitting on the opposite side and if, at that time, it was